नई दिल्ली
शनिवार
24 अक्टूबर 2026
वर्षः 13, अंकः 50
पृष्ठः 08, मूल्य 2 रु0

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की

डॉ हेडगेवार जी के जीवन, त्याग, अनुशासन एवं...पेज-05

DELHIN/2014/58158

सनातन चेतना, जन आस्था और वैश्विक गौरव...पेज-08

एक नजर

संसद परिसर में रानी चेन्नम्मा की जयंती और 202वीं विजय वर्षगांठ मनाई गई

नई दिल्ली। संसद परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर शुक्रवार को कित्तूर की वीरांगना रानी चेन्नम्मा की जयंती और अंग्रेजों के खिलाफ उनकी ऐतिहासिक विजय की 202वीं वर्षगांठ भव्यता के साथ मनाई गई। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और रेल एवं जल शक्ति राज्यमंत्री वी. सोमन्ना सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने रानी चेन्नम्मा को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके शौर्य और बलिदान को याद किया। रेल एवं जल शक्ति राज्यमंत्री तथा तुमकुरु के सांसद वी. सोमन्ना के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में सांसद पी.सी. मोहन, डॉ. सुधाकर, कर्नाटक के पूर्व मंत्री मुरुगेश निरानी और बसनगौड़ा पाटिल यतनाल सहित कई प्रमुख व्यक्ति शामिल हुए। इस अवसर पर कर्नाटक के विभिन्न जिलों और दिल्ली में रहने वाले कन्नड़ समुदाय के लोगों ने भी रानी चेन्नम्मा को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में विभिन्न मठों के संत भी उपस्थित रहे। इनमें कुडलसंगम के बसव मृत्युंजय स्वामी, शंकरानंद स्वामी, बीदर के आलुर स्थित सिद्धारूढ़ मठ के संत, कक्कमारी के गुरुदेव आश्रम के आत्माराम स्वामी और चलकापुरा के सिद्धारूढ़ मठ के विनायक स्वामी शामिल थे।

इस अवसर पर सोमन्ना ने रानी चेन्नम्मा को देश की अद्वितीय वीरांगना बताते हुए कहा कि उन्होंने केवल एक युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि साम्राज्यवादी सत्ता को चुनौती दी। उनका नाम इतिहास में प्रतिरोध और अदम्य साहस के अमर प्रतीक के रूप में दर्ज है। ऐसी वीर महिला की उपलब्धियों का स्मरण करना सभी के लिए गर्व और प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने कहा कि संसद के इस पवित्र परिसर में वीरांगना रानी चेन्नम्मा का शौर्य और साहस आज देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। अपनी मातृभूमि और भाषा से प्रेम करने वाले सभी लोगों के लिए उनका जीवन गर्व का विषय है। उन्होंने लोगों से हर वर्ष एकत्र होकर ऐसी महान विभूतियों को याद करने की अपील की।

दवा कंपनियों की अनैतिक गतिविधियों पर लगेगा अंकुश

नई दिल्ली। दवा कंपनियों की मार्केटिंग में अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग की ओर से गठित यह समिति दवा कंपनियों और स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच होने वाले व्यावसायिक संपर्कों से जुड़े मौजूदा नियमों की व्यापक समीक्षा करेगी। समिति को अपनी पहली बैठक की तारीख से दो महीने के भीतर सिफारिशें सौंपनी होंगी। नीति आयोग के सदस्य डॉ. एम. श्रीनिवास को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके सदस्यों में पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन और मेदांता के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. नरेश त्रेहान शामिल हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि समिति दवा कंपनियों की मार्केटिंग से जुड़ी अनैतिक गतिविधियों की पहचान करने के साथ मौजूदा निगरानी, नियंत्रण और नियमों के अनुपालन की व्यवस्था की प्रभावशीलता का आकलन करेगी। इसका उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना तथा नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना है। समिति यह भी विचार करेगी कि मौजूदा नियामकीय ढांचे को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त कानूनी या वैधानिक प्रावधानों की जरूरत है या नहीं।

विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका अहमः प्रधानमंत्री

पीएम मोदी ने चिन्मय अमृत महोत्सव वैश्विक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया

नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवाओं को देश की प्रगति से जोड़ना, समाज को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट करना और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक करना जरूरी है। मोदी आज यहां चिन्मय अमृत महोत्सव वैश्विक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने चिन्मय मिशन से विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वामी चिन्मयानंद जी का मुख्य विचार युवाशक्ति के निर्माण के जरिए सशक्त भारत बनाना था। चिन्मय मिशन के युवा कार्यकर्ताओं ने करीब 300 दिनों में 40 हजार किलोमीटर की यात्रा कर एक लाख से अधिक युवाओं से संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि 2047 में देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे और इसी कालखंड में चिन्मय मिशन भी अपनी शताब्दी मनायेगा। ऐसे में विकसित भारत और चिन्मय मिशन की यात्रा को साथ आगे बढ़ाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि मिशन के संत, आचार्य, साधक और कार्यकर्ता विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभायेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी चिन्मयानंद जी ने भारतीय ज्ञान, संस्कृति और विरासत को जन-जन तक पहुंचाने का काम किया। चिन्मय मिशन के 100 से अधिक शिक्षण संस्थान बच्चों और युवाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आध्यात्मिक उन्नति को व्यक्तिगत विकास और व्यक्तिगत विकास को राष्ट्र की प्रगति से जोड़ने की सीख देते थे। श्री मोदी ने नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा, मातृभाषा में शिक्षा, आधुनिक विज्ञान और नयी तकनीक को महत्व दिया गया है।

उन्होंने कहा कि देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और उसके प्रति गर्व की भावना को मजबूत करना जरूरी है। काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में राम मंदिर और उज्जैन के महाकाल महालोक जैसे केंद्रों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के सांस्कृतिक केंद्रों का पुनर्जागरण हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 12 वर्षों में विदेशों में चोरी कर ले जायी गयी 650 से अधिक प्राचीन मूर्तियों को वापस लाया गया है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग संस्थाओं के उद्देश्य भले ही अलग हों, लेकिन देश का विकास और गौरव सभी का साझा लक्ष्य है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी को मिलकर आगे बढ़ना होगा।

अगले 20-30 साल की चुनौतियों के लिए तैयार रहे सेनाः राजनाथ

नई दिल्ली,एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि लंबे समय की रणनीतिक सोच के साथ काम करने और आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बराबर तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने 'लैंड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन' लॉन्च किया और यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग मिशन में बेहतरीन सेवा के लिए तीन भारतीय सेना के जवानों को सम्मानित भी किया। रक्षा मंत्री ने मॉडर्न युद्ध के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बात कही और जोर दिया कि सफलता मल्टी-डोमेन क्षमताओं और जॉइंट ऑपरेशन में आसान तालमेल पर निर्भर करेगी।

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने नई सोच और बेहतर तालमेल दिखाया, साथ ही एडवांस्ड हथियारों का भी इस्तेमाल किया। रक्षा मंत्री ने आर्मी कमांडरों से जियोपॉलिटिकल और क्षेत्रीय डेवलपमेंट पर करीब से नजर रखने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने अगले 20-30 सालों के लिए एक लंबे समय के स्ट्रेटेजिक विज़न की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और भारतीय सेना के सीनियर लीडरशिप से तुरंत और नई चुनौतियों का जवाब देने के लिए समान रूप से तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजी डायनैमिक और फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए, ताकि बदलते हालात के हिसाब से समय पर बदलाव किए जा सकें। बदलते ऑपरेशनल हालात के हिसाब से खुद को ढालने के लिए डिफेंस फोर्स की तारीफ करते हुए राजनाथ सिंह ने बताया कि नई सोच और बेहतर तालमेल के साथ-साथ एडवांस्ड हथियारों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में योगदान दिया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन से यह साफ संदेश गया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाने में नहीं हिचकिचाएगा। उन्होंने क्षमताओं को मजबूत करने, लगातार परफॉर्मेंस का आकलन करने और बदलते हालात के हिसाब से जरूरी सुधार लागू करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनॉमस सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क जैसे क्षेत्रों में कोशिशों में तेजी लाने के महत्व पर जोर दिया। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि हवा, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर डोमेन में चुनौतियों के बढ़ते महत्व के बावजूद जमीनी युद्ध और जमीनी सेनाएं जरूरी बनी रहेंगी। उन्होंने मॉडर्न युद्ध के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की अपील की और ज़ोर दिया कि सफलता मल्टी-डोमेन क्षमताओं और जॉइंट ऑपरेशन में बिना रुकावट के तालमेल पर निर्भर करेगी। रक्षा मंत्री ने डिफेंस फोर्स की आत्मनिर्भरता की कोशिशों को माना और कहा कि भारत की बढ़ती डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं सभी स्टेकहोल्डर्स की मिलकर की गई कोशिशों का नतीजा हैं।

नई तकनीक का लाभ पूरी मानवता को मिले, किसी एक देश तक सीमित न रहेः उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली,एजेंसी। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने शुक्रवार को कहा कि नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ पूरी मानवता को मिलना चाहिए, न कि उन्हें किसी एक देश की विशिष्ट संपत्ति तक सीमित रखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि 'भारत का लाभ मानवता का लाभ है' और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य केवल आकांक्षा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, जिसे पूरा करने के लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उपराष्ट्रपति ने यहां उपराष्ट्रपति भवन में अनिल के. एंटनी की पुस्तक 'एडवांटेज इंडिया: रीशेपिंग द फ्यूचर फॉर एन इक्विटेबल वर्ल्ड' का विमोचन करते हुए ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने पुस्तक के प्रकाशन के लिए लेखक और रूपा पब्लिकेशंस को बधाई देते हुए कहा कि इसमें भारत के उल्लेखनीय परिवर्तन और तेजी से बदलती दुनिया में देश के सामने मौजूद अवसरों को रेखांकित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी, कारोबार और सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में अपने अनुभव के आधार पर लेखक ने भारत की उभरती क्षमताओं और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में देश की बढ़ती भूमिका का विश्लेषण किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक परंपराएं, जनसांख्यिकीय लाभांश, बढ़ती अर्थव्यवस्था, मजबूत संस्थान और विस्तारित तकनीकी क्षमताएं देश की विशिष्ट ताकत हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि 25 करोड़ से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। शिक्षा, आवास, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी पहलों ने लाखों नागरिकों के जीवन में गरिमा और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया है। राधाकृष्णन ने कहा कि समावेशी विकास भारत की प्रगति का प्रमुख आधार है और महिलाओं, युवाओं, किसानों तथा वंचित वर्गों का सशक्तीकरण इसमें केंद्रीय भूमिका निभाता है।

सेना के प्रशिक्षण से मजबूत होगा देश का नागरिक सुरक्षा नेटवर्क

नई दिल्ली। देश में नागरिक सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए भारतीय सेना और केंद्रीय गृह मंत्रालय संयुक्त प्रशिक्षण पहल शुरू करने जा रहे हैं।

इसके पहले चरण में 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 600 नागरिक सुरक्षा मास्टर ट्रेनरों को नवंबर के दूसरे सप्ताह में तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल के तहत प्रशिक्षित प्रत्येक मास्टर ट्रेनर अपने राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में 100 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करेगा। इससे कुल 60 हजार स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप देश में आधुनिक प्रणालियों, तकनीक और समकालीन सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की क्षमता से लैस एक सशक्त नागरिक सुरक्षा नेटवर्क विकसित किया जा रहा है।

बिहारः सीवान जिले के आलमापुर पटाखा विस्फोट में करीब 7 की मौत, 05 की एसपी ने की पुष्टि

सीवान,एजेंसी। बिहार में सीवान जिले के आलमपुर गांव में पटाखा बनाने के दौरान हुए विस्फोट में करीब 07 लोगों की मौत हो गई। सीवान के पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अभी तक 05 लोगों के शव को बरामद किया गया है, जबकि अ्य लोग अभी अन्दर हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम और एफएसएल की टीम जांच कर रही है, उनकी रिपोर्ट के बाद ही सही जानकारी मिलेगी। फिलहाल 05 की डेडबॉडी मिल गई है।

ग्रामीणों के अनुसार, मृतकों में एक ही परिवार के पांच लोग शामिल हैं। पटाखा कारोबारी अमीरुद्दीन, इनकी तीन पोतियां, एक पोता के अलावा दो मजदूरों की बात सामने आई है। हालांकि सीवान के डीएम विजय प्रकाश मीणा और एसपी भरत सोनी ने कहा कि अभी तक 05 लोगों के ही शव बरामद किए जा सके हैं। अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका है। बचाव दल घर में प्रवेश कर रहा है। पूरी तरह छानबीन के बाद ही सही संख्या का पता चल पाएगा। धमाका शाम करीब साढ़े 5 बजे हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई। तेज धमाकों की आवाज से दहशत फैल गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। किसी को यह पता नहीं चल रहा था कि विस्फोट किधर हुआ है। बाद में लोगों को पता चला कि पटाखा कारोबारी अमीरूद्दीन के घर में ही विस्फोट हुआ है। बताया गया है कि शुक्रवार को रोजाना की तरह घर के भीतर पटाखे बनाए जा रहे थे। इसी दौरान अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पटाखों में विस्फोट होने लगे। लगातार हो रहे धमाकों से मकान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। विस्फोट इतना भयावह था कि तीन लोगों के शव बुरी तरह क्षत-विक्षत होकर घर के बाहर जा गिरे। घटनास्थल का दृश्य बहुत ही भयावह नजर आया। इस घटना के बाद पूरे गांव में खौफ का माहौल है। एसपी ने बताया कि घटनास्थल पर पुलिस, अग्निशमन विभाग, मेडिकल टीम और बिजली विभाग की टीमें पहुंच गयी हैं। फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम भी घटनास्थल से नमूने एकत्र कर जांच करेगी। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गयी है। ग्रामीणों से घटनास्थल से कम से कम 200 मीटर दूर रहने की अपील की गयी है, क्योंकि वहां अब भी रुक-रुककर विस्फोट हो रहे हैं। एसपी भारत सोनी ने कहा कि घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जायेगी। जांच में यह पता लगाया जायेगा कि पटाखे बनाने के लिए विस्फोटक सामग्री कहां से लायी जाती थी और संबंधित लोगों के पास वैध लाइसेंस था या नहीं। ग्रामीणों ने बताया है कि पटाखा निर्माण से जुड़े लोग पहले लाइसेंसधारी थे और करीब 20 वर्षों से इस कारोबार में लगे थे।

एलएसी पर गलतफहमी से बचने के लिए भारत और चीन के बीच विभिन्न स्तर पर चल रही है बातचीतः विदेश मंत्रालय

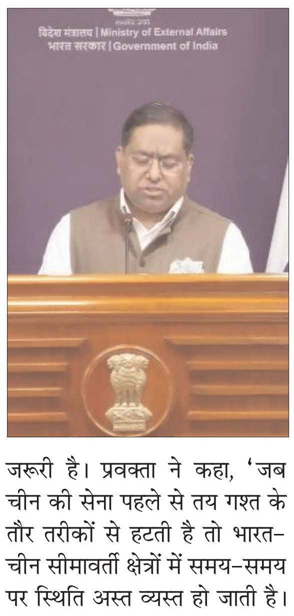

नई दिल्ली,एजेंसी। अरूणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों में भारत और चीन की सेनाओं में टकराव की घटनाओं की खबरों के बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन की सेना के तय गश्त के तौर तरीकों से हटने के कारण समय-समय पर सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति अस्त-व्यस्त हो जाती है और गलतफहमी तथा गलत आकलन से बचने के लिए दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तर पर बातचीत चल रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को यहां मीडिया ब्रीफिंग में इस संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि भारत का दृढता से यह मानना है कि द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत जरूरी है। प्रवक्ता ने कहा, 'जब चीन की सेना पहले से तय गश्त के तौर तरीकों से हटती है तो भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में समय-समय पर स्थिति अस्त व्यस्त हो जाती है।

दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए तथा गलतफहमी और गलत आकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य तंत्र का उपयोग जारी रखे हुए हैं।

दोनों पक्षों ने बेहतर सीमा प्रबंधन के लिए उपयुक्त क्षेत्रों में एलएसी की समझ को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा करने पर भी सहमति बनाई है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत जरूरी है। 'उल्लेखनीय है कि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा है कि अरूणाचल प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में भारत और चीन के सैनिक आमने- सामने हुए हैं और कुछ मौकों पर टकराव की स्थिति भी बनी है जो अभी भी जारी है।

मल्लिकार्जुन खरगे ने चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा

अरुणाचल में चीन के साथ टकराव पर सच छिपा रही है सरकार, देश को दी जाए पूरी जानकारी

नई दिल्ली,एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना के साथ भारतीय सैनिकों के टकराव की जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें देश को गुमराह करने की बजाय संसद तथा जनता को पूरा सच बताना चाहिए।

खरगे ने शुक्रवार को यहां एक बयान में कहा कि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के साथ लगातार हो रहे टकराव की पुष्टि की है। उन्होंने पूछा कि डोकलाम और गलवान के बाद क्या यह एक और गंभीर टकराव हो रहा है। उनका यह भी कहना था कि अगस्त में तक्सिंग के पास चीनी घुसपैठ की खबरें आई थीं और वाचा-दमाई में कोर कमांडर स्तर की वार्ता के 47 दिन बाद भी टकराव जारी रहने की खबरें हैं। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और इस मामले में देश को अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि क्या भारत की गश्त करने की पहुंच इस क्षेत्र में प्रभावित हुई है। श्री खरगे ने प्रधानमंत्री से चीन को बार-बार क्लीन चिट देना बंद करने और देश के सामने स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में जवाबदेही जरूरी है, न कि कूटनीतिक मुलाकातें और गले मिलना। चीन पर आर्थिक निर्भरता को लेकर उन्होंने कहा कि गलवान में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद वित्त वर्ष 2020-21 से चीन से आयात में 102 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 112.16 अरब डॉलर हो गया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वीकार कर चुकी हैं कि चीन भारतीय निर्यात में बाधा डालता है। उन्होंने चीन से जुड़े निवेश पर प्रतिबंधों में ढील देने और पात्र चीनी कंपनियों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) का लाभ देने पर विचार किए जाने का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि क्या 'मेक इन इंडिया' अब 'इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना' बन गया है। श्री खरगे ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कम से कम 23 बैठकें और बातचीत हुई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भागीदारी में विशेष प्रतिनिधियों की 25 दौर की वार्ताएं हुई हैं और सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्यकारी तंत्र (डब्ल्यूएमसीसी) की 36 बैठकें हुई हैं। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) और ब्रिक्स के शिखर सम्मेलनों में भी दोनों पक्षों के बीच संपर्क हुआ है। बैठकों के क्या ठोस परिणाम निकले और क्या मई 2020 से पहले की गश्त संबंधी पहुंच पूरी तरह बहाल हुई है। हमको सशस्त्र बलों पर पूरा भरोसा है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में जवाबदेही भी जरूरी है। प्रधानमंत्री को विपक्ष पर हमला करने की बजाय संसद और देश की जनता को पूरी स्थिति से अवगत कराना चाहिए। ' इस बीच, कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार जून-जुलाई से अरुणाचल प्रदेश में चीन की गतिविधियों से जुड़ी खबरों को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आईटीबीपी के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने अब पुष्टि की है कि भारतीय सैनिकों और चीनी सेना के बीच टकराव जारी है।

दिल्ली के 4,000 एमटीएस जनस्वास्थ्य कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, मुख्यमंत्री ने खातों में भेजी बढ़ी हुई राशि

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के लगभग 4,000 एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ) जनस्वास्थ्य कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के निर्णय के तहत मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने बढ़ी हुई वेतन राशि कर्मचारियों के खातों में हस्तांतरित की। इस अवसर पर दिल्ली नगर निगम मुख्यालय स्थित केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि दिल्ली की सेवा करने वाले हजारों कर्मचारियों के हितों और कल्याण की चिंता करना सरकार का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार उन सभी कर्मचारियों के सम्मान, अधिकारों और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, जो दिन-रात दिल्लीवासियों की सेवा में जुटे रहते हैं। उन्होंने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के दशकों के समर्पण, संघर्ष और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का सम्मान है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वर्ष 1996 में दिल्ली में डेंगू के प्रकोप के दौरान नियुक्त किए गए इन कर्मचारियों ने लंबे समय से घर-घर जाकर नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके योगदान को उचित सम्मान देना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल व्यवस्थाओं में सुधार करना नहीं, बल्कि उन कर्मचारियों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाना है, जो इन व्यवस्थाओं को जमीन पर उतारते हैं। कर्मचारियों को उनके काम के अनुरूप सम्मान, सुरक्षा और सुविधाएं मिलने से उनका मनोबल बढ़ता है तथा वे अधिक उत्साह से जनसेवा कर पाते हैं। मुख्यमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कर्मियों के मानदेय तथा नर्सिंग इंटर्न के मासिक स्टाइपेंड में वृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि जनसेवा से जुड़े कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कर्मचारियों से जनता के साथ विनम्रता, संवेदनशीलता और सेवाभाव से व्यवहार करने की अपील भी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली के महापौर श्री प्रवेश वाही ने कहा कि दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार की विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने में सहयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि एमटीएस जनस्वास्थ्य कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखा गया था। इस पर मुख्यमंत्री ने पूछा कि इस निर्णय को लागू करने में कितना खर्च आएगा। महापौर के अनुसार, उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रतिवर्ष लगभग 52 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जिस पर मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान कर दी।

महापौर ने कहा कि अब बढ़ी हुई राशि कर्मचारियों के खातों में भेजी गई है। उन्होंने इस निर्णय का श्रेय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व को दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निगम कर्मचारियों से ऐसी कार्यशैली अपनाने का आह्वान किया है, जिससे निगम के कार्यों की सराहना हो। महापौर ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि निगम कर्मचारी बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रयासरत रहेंगे। महापौर प्रवेश वाही ने घोषणा की कि दीवाली के अवसर पर दिल्ली की सड़कों और बाजारों को साफ-सुथरा रखने के उद्देश्य से 2,500 नए स्वच्छता कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार यह कदम उठाया जा रहा है, ताकि आगामी त्योहारों के दौरान राजधानी में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। महापौर ने दावा किया कि नियुक्तियों की प्रक्रिया में विपक्ष की ओर से बाधाएं डालने की कोशिश की गई, लेकिन निगम अपने उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान दिल्ली के बाजारों और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता सुनिश्चित करना निगम की प्राथमिकता है। दिल्ली नगर निगम में नेता सदन श्री जय भगवान यादव ने जनस्वास्थ्य कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली में विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल में कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर भी आलोचनात्मक टिप्पणी की और कहा कि वर्तमान सरकार के दौरान महीने की पहली तारीख को वेतन मिलना सामान्य व्यवस्था बन गई है।

प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान कर समयबद्ध कार्रवाई करें अधिकारी: सिरसा

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को अधिकारियों को दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम दिल्ली के प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान कर समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने यातायात जाम, सड़क की धूल, अतिक्रमण, खुले में कूड़ा जलाने और निर्माण गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने पर जोर दिया। कापसहेड़ा स्थित जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में सिरसा ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने और प्रत्येक चिन्हित स्थान के लिए स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी, पुलिस, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), मेट्रो, रेलवे, यातायात पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) निगरानी केंद्रों से प्राप्त आंकड़ों और जमीनी निरीक्षण के आधार पर प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से प्रत्येक हॉटस्पॉट पर प्रदूषण के संभावित स्रोतों का आकलन करने, जिम्मेदार एजेंसी निर्धारित करने और सुधारात्मक कार्रवाई की समयसीमा तय करने को कहा। उन्होंने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर पीएम10 और पीएम2.5 के स्तर की निगरानी की जाए तथा अधिक प्रदूषण वाले क्षेत्रों में लक्षित निरीक्षण कर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। सिरसा ने अधिकारियों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के पहले चरण के तहत लागू प्रदूषण नियंत्रण उपायों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मंत्री ने निर्माण एवं मलबा संग्रहण स्थलों पर धूल नियंत्रण के निर्धारित मानकों का पालन कराने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने खुले में कूड़ा, जैविक अपशिष्ट, प्लास्टिक और रबर जलाने पर रोक प्रभावी ढंग से लागू करने तथा कचरे के उचित संग्रह, पृथक्करण, परिवहन और निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सिरसा ने कहा कि यातायात जाम और धीमी गति से चलने वाले वाहनों के कारण उत्सर्जन बढ़ता है। उन्होंने यातायात पुलिस और संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ भारी वाहनों की आवाजाही सुचारु बनाने, व्यस्त समय में अनावश्यक जाम रोकने तथा अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने दिल्ली की सीमाओं से आने वाले गैर-दिल्ली भारी वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित करने और राजधानी के भीतर भारी वाहनों के परिचालन को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने पर भी जोर दिया। मंत्री ने अधिकारियों को सड़कों से अवैध अतिक्रमण हटाने, गड्ढों की मरम्मत करने और सड़क किनारे खुले मिट्टी वाले क्षेत्रों का उपचार करने के निर्देश दिए।

कोर्ट का पुलिस को निर्देश- चंद्रशेखर के खिलाफ 2 नवंबर तक पूरी करें जांच

नई दिल्ली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ दर्ज रेप केस में दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करने के लिए पांच कार्य दिवस का समय देने की मांग की है। दिल्ली पुलिस की इस मांग का शिकायतकर्ता ने विरोध किया, जिसके बाद एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को करने का आदेश दिया। इसके पहले कोर्ट ने जांच अधिकारी को 23 अक्टूबर को हर हाल में जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। इसके लिए कोर्ट ने सम्बन्धित डीसीपी को नोटिस जारी करते हुए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि एक दलित एक्टिविस्ट युवती ने चंद्रशेखर आजाद पर शादी का वादा करके यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। उसके वकील ने कोर्ट से चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की।

कोर्ट ने 18 अगस्त को दिल्ली पुलिस को एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। उसके बाद दो सितंबर को जांच अधिकारी ने कहा कि उसे शिकायत की कापी नहीं मिली है, इसलिए जांच शुरू नहीं की जा सकी। 18 सितंबर को कोर्ट ने 5 अक्टूबर तक जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन आज भी जांच अधिकारी की ओर से समय मांगे जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और 23 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।

दिल्ली के अन्य नालों के किनारों को हरा-भरा और सुरक्षित बनाने की दिशा में काम करेंगे : प्रवेश साहिब

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी एवं जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली के अन्य नालों के किनारों को हरा-भरा, स्वच्छ और सुरक्षित बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, पीडब्ल्यूडी एवम जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने यह बात आज दिल्ली सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता के दौरान कही। दिल्ली में हर साल मानसून के दौरान पैदा होने वाली जलभराव और बाढ़ की विकराल समस्या के स्थायी समाधान के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सचिवालय में आयोजित 40वीं फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक में दिल्ली की जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 622 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

उन्होंने कहा, 'नाले गंदगी और बदहाली की पहचान नहीं, बेहतर शहरी विकास का हिस्सा बनने चाहिए। बरापुला में जिस तरह नाले के किनारे के क्षेत्र को विकसित किया गया है, उसी तर्ज पर दिल्ली के अन्य नालों के किनारों को भी हरा-भरा, स्वच्छ और सुरक्षित बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि नालों की गाद निकालने का कोई मतलब नहीं है, अगर वही गाद वापस नालों में पहुंच जाए। वर्षों से यही समस्या बनी हुई थी। बायोमाइनिंग के माध्यम से गाद का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा, ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। बोर्ड ने मैगजीन रोड नाले से ओल्ड रेलवे ब्रिज तक यमुना के संवेदनशील हिस्से में 99 करोड़ रुपये की लागत से 4.7 किलोमीटर लंबी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) दीवार बनाने को मंजूरी दी। इससे यमुना का जलस्तर बढ़ने के दौरान निचले इलाकों को सुरक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी। दिल्ली में हर साल नालों की सफाई और डी-सिल्टिंग के दौरान बड़ी मात्रा में गाद निकाली जाती है। लेकिन इस गाद का उचित निस्तारण लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रहा है। वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था नहीं होने के कारण कई बार निकाली गई गाद नालों के किनारे या सड़कों पर पड़ी रहती है और बारिश के दौरान दोबारा नालों में पहुंच जाती है। इससे सफाई के प्रयासों पर भी असर पड़ता है। इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में बोर्ड ने दिल्ली के विभिन्न नालों से निकलने वाली गाद के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और निस्तारण के लिए 260 करोड़ रुपये की लागत वाली तीन बायोमाइनिंग परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से विशेष रूप से नजफगढ़ नाले सहित दिल्ली के उन प्रमुख नालों को लाभ होगा, जहां गाद का जमाव अधिक होता है। बैठक में दिल्ली के विभिन्न नालों के किनारे बरापुला की तर्ज पर सौंदर्यीकरण और विकास कार्य करने पर भी चर्चा की गई।

राष्ट्रीय स्कूल खेल देश के भविष्य के खेल इकोसिस्टम को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है: आशीष सूद

नई दिल्ली। दिल्ली के शिक्षा एवं खेल मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय स्कूल खेल केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि देश के भविष्य के खेल इकोसिस्टम को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। आशीष सूद ने यह बात आज त्यागराज स्टेडियम में शुक्रवार को 70वें राष्ट्रीय स्कूल खेल 2026-27 का उद्घाटन के अवसर पर कही। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (खेल शाखा) की ओर से स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) के तत्वावधान में इन खेलों का आयोजन तीन चरणों में किया जाएगा। इनमें पहले चरण में 22 से 28 अक्टूबर, दूसरे चरण में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर और तीसरे चरण में 28 जनवरी से 3 फरवरी शामिल हैं। इन खेलों में कुल 14 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, जिसमें देशभर से 14 हजार से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी शामिल होंगे। देशभर से आए युवा एथलीटों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल मंत्री ने कहा, जीत से भी अधिक महत्वपूर्ण खेल भावना, अनुशासन, मित्रता और चरित्र निर्माण है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में 'खेलो इंडिया' और 'फिट इंडिया' जैसे अभियानों ने देश में खेल संस्कृति को नया आयाम दिया है। पहले कहा जाता था 'खेलोगे-कूदोगे तो होगे खराब', लेकिन अब बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाओं और आर्थिक प्रोत्साहन के बल पर युवा खेलों में भी एक सफल और उज्ज्वल भविष्य बना रहे हैं।

बाहर से आने वाली टीमों के ठहरने, भोजन, सुरक्षा, परिवहन और चिकित्सा सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। स्टेडियमों और खेल परिसरों में अंतरराष्ट्रीय स्तर के ट्रैक, फील्ड और उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं ताकि खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खेल माहौल मिल सके। शिक्षा मंत्री ने बताया कि दिल्ली में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ढांचागत और वित्तीय सहयोग को मजबूत किया जा रहा है। ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि में से स्वर्ण पदक पर 7 करोड़ रुपये, रजत पर 5 करोड़ रुपये और कांस्य पदक पर 3 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि तय की गई है। एशियाई और अन्य अंतरराष्ट्रीय खेलों के विजेताओं के लिए भी आकर्षक प्रावधान हैं। पीतमपुरा में करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किया जा रहा है। दिल्ली के कॉलेजों को मिलने वाले खेल अनुदान को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। दिल्ली में पिछले वर्ष आयोजित खेलो महाकुंभ में 16 हजार से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसके अलावा त्यागराज स्टेडियम में 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का भी सफल आयोजन किया जा चुका है। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रख्यात खिलाड़ी और देशभर के राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

दिल्ली के 48 गांवों को शहरी दर्जा देने का फैसला, सुनियोजित विकास का रास्ता होगा साफ: रेखा गुप्ता

शबाना बेगम , सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि राजधानी के 48 गांवों को शहरीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इससे इन गांवों में सड़क, सीवर, जलापूर्ति और अन्य नागरिक सुविधाओं के सुनियोजित विकास की योजना बनाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय दिल्ली के बदलते शहरी स्वरूप के अनुरूप विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य गांवों की सांस्कृतिक विरासत और पहचान का सम्मान करते हुए उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। सरकार के अनुसार, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 507(ए) के तहत इन गांवों को शहरीकृत करने का निर्णय लिया जा रहा है। इस पहल से संबंधित क्षेत्रों की वैधानिक स्थिति स्पष्ट करने और उनके भविष्य के विकास की योजना तैयार करने के लिए आधार मिलेगा। यह प्रक्रिया मास्टर प्लान-2041 के मसौदे के अनुरूप विकास की संभावनाओं का आकलन करने में भी सहायक होगी। शहरीकरण के दायरे में आने वाले गांवों में बकौली, हमीदपुर, पल्ला, कुलकपुर, सिंघोला, सुंगरपुर दिल्ली, सुंगरपुर शाहदरा,

ताजपुर कलां, टिहरी दौलतपुर, राजपुर कलां, औचंदी, मुंगेशपुर, शाहपुर गढ़ी, निजामपुर रसिदपुर, चटेसर, पुर दिल्ली, जगतपुर दिल्ली, सुल्तानपुर माजरा, पुर शाहदरा, सबापुर दिल्ली, बदरपुर खादर, बाकीआबाद, खानपुर खानी, जाफराबाद, जगतपुर शाहदरा और बदरपुर माजरा बुराड़ी शामिल हैं। इसके अलावा फतेहपुर बेरी, चंदनहोला, बदूसराय, देवराला, घुम्मनहेड़ा, जैनपुर, झटिकरा, कांगनहेड़ी, राघोपुर, रावता, शिकारपुर, बिजवासन, नानक हेड़ी, बकरगढ़, ढांसा, गालिबपुर, इस्सापुर, कैर, मुंडेला कलां, मुंडेला खुर्द, सुरखपुर और चक चिल्ला को भी शहरीकृत किए जाने वाले गांवों की सूची में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इन गांवों के शहरीकरण से भूमि उपयोग, आंतरिक सड़कों और संपर्क मार्गों, जलापूर्ति, सीवर नेटवर्क, जल निकासी, स्वच्छता तथा कचरा प्रबंधन जैसी सुविधाओं की जरूरतों का व्यवस्थित आकलन करने में मदद मिलेगी। संबंधित नागरिक एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाएं तैयार करने का अवसर मिलेगा।

सरकार ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद संबंधित गांवों का दर्जा ग्रामीण से शहरी हो जाएगा। इससे इन क्षेत्रों पर लागू कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों को लेकर स्पष्टता आएगी तथा भविष्य की विकास योजनाओं के लिए कानूनी आधार उपलब्ध होगा। हालांकि, शहरीकरण के निर्णय से अपने आप निर्माण या भूमि उपयोग में बदलाव की अनुमति नहीं मिलेगी। ऐसे कार्यों के लिए संबंधित नियमों, भवन विनियमों, स्वीकृत योजनाओं और आवश्यक वैधानिक मंजूरियों का पालन करना होगा। विकास कार्यों के लिए आगे की कार्रवाई संबंधित विभागों और नागरिक एजेंसियों द्वारा लागू नीतियों, उपलब्ध संसाधनों तथा स्वीकृत योजनाओं के अनुरूप की जाएगी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की नेहा बोरा की याचिका, बेल बॉन्ड के नोटिस को दी थी चुनौती

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आईसा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा की दिल्ली पुलिस की ओर से जारी नोटिस के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। याचिका में नेहा बोरा ने दस हजार रुपये के निजी मुचलका भरने और शांति बनाए रखने का निर्देश देने वाले आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने 22 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान नेहा बोरा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा था कि नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने कहा था कि सवाल यह है कि क्या इस नोटिस में कोई दम है? हमें राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। पुलिस को कानून की क्लास लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 और 130 के तहत नोटिस से जुड़ा एक बहुत ही सीमित मामला है। याचिकाकर्ता आईसा की एक नेता हैं और सार्वजनिक जीवन में काफी सक्रिय है। असल में, समय-समय पर देश में कुछ विरोध-प्रदर्शन हुए हैं, जो सरकार के फैसलों के खिलाफ थे। जहां तक मेरे मुवक्किल की बात है, तो उन्होंने कभी हिंसा के लिए उकसाया नहीं है, उनके सभी विरोध-प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहे हैं। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एएसजी चेतन शर्मा ने बोरा की याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि कानून हमें धारा 126 और 130 को एक साथ लागू करने की अनुमति देता है। शांति भंग होने की संभावना है। इसे सिर्फ तकनीकी बारीकियों पर न छोड़ें। दिल्ली में भारी अफरा-तफरी मच सकती है। यह एक एहतियाती कदम है, ताकि कानून का असर ठीक उसी तरह हो जैसा संसद ने सोचा था। दरअसल, दिल्ली पुलिस ने 18 अक्टूबर को बोरा को नोटिस जारी कर उन्हें 19 अक्टूबर को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का निर्देश दिया था।

प्रदूषण के खिलाफ एमसीडी की सख्त कार्रवाई, तीन औद्योगिक इकाइयां सील

एम. जबिउल्लाह, सद्भावना टुडे

पश्चिमी क्षेत्र में संयुक्त अभियान, बिजली कनेक्शन काटे और मीटर जब्त, सात इकाइयों का किया गया निरीक्षण

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने सख्त रुख अपनाते हुए पश्चिमी क्षेत्र में संयुक्त सर्वेक्षण एवं सीलिंग अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान प्रदूषण फैलाने वाली तीन औद्योगिक इकाइयों को सील कर दिया गया। साथ ही, संबंधित इकाइयों के बिजली कनेक्शन काटने के अलावा बिजली के मीटर भी जब्त किए गए। एमसीडी के पश्चिमी क्षेत्र की ओर से यह अभियान राजस्व विभाग, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), बीएसईएस और दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर चलाया गया। ब्रह्मपुरी और चंचल पार्क सहित संबंधित क्षेत्रों में की गई इस कार्रवाई के अंतर्गत वार्ड संख्या 110 (कुंवर सिंह नगर) और वार्ड संख्या 111 (बापरोला) में सघन निरीक्षण किया गया।

सात इकाइयों की जांच, तीन पर कार्रवाई

संयुक्त टीम ने अभियान के दौरान कुल सात इकाइयों का निरीक्षण किया। इनमें छह औद्योगिक इकाइयां और एक गोदाम शामिल था। निरीक्षण के दौरान प्रदूषण फैलाने वाली तीन औद्योगिक इकाइयों की पहचान की गई, जिन्हें नियमानुसार मौके पर ही सील कर दिया गया। कार्रवाई को

प्रभावी बनाने के लिए संबंधित इकाइयों के बिजली कनेक्शन भी काटे गए और बिजली के मीटर जब्त कर लिए गए। इस कदम का उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाना और नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

विभागों के समन्वय से प्रदूषण पर लगाम लगाने की पहल

एमसीडी के पश्चिमी क्षेत्र का यह अभियान प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के संयुक्त प्रयासों को दर्शाता है। अभियान में शामिल विभागों के बीच समन्वय के माध्यम से प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए औद्योगिक गतिविधियों की निगरानी और नियमों का पालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। ऐसे संयुक्त अभियानों से प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियमों के अनुपालन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सद्भावना टुडे की रिपोर्ट: प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि संबंधित विभाग नियमित निरीक्षण जारी रखें और नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ निष्पक्ष एवं नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।

नस्लीय टिप्पणी मामले में यूट्यूबर आमिर शौकीन एक दिन की न्यायिक हिरासत में

नई दिल्ली। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने नस्लीय टिप्पणी से जुड़े एक मामले में कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने आमिर शौकीन की छह दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की थी। दिल्ली पुलिस ने आमिर शौकीन को 22 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। शौकीन को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, जिन्होंने निर्देश दिया कि उन्हें सुनवाई के लिए संबंधित नियमित कोर्ट में पेश किया जाए। उन्हें कल फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले में सदर बाजार पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। त्रिपुरा की पुलिस ने भी इस मामले में अलग से एफआईआर दर्ज की है। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर एक कंटेंट क्रिएटर द्वारा त्रिपुरा के एक व्यक्ति के खिलाफ नस्लीय टिप्पणियां की जा रही हैं और उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है। त्रिपुरा पुलिस ने 22 अक्टूबर को पश्चिम त्रिपुरा जिले के न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन में शौकीन के खिलाफ मामला दर्ज किया। यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी कानून और एससी-एसटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत है। इस मामले में त्रिपुरा पुलिस की टीम दिल्ली पहुंच चुकी है। त्रिपुरा पुलिस आमिर शौकीन की ट्रांजिट रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। पुलिस के मुताबिक आमिर शौकीन ने एक महीने पहले अहमदाबाद में ये विवादित वीडियो बनाया था।

एक नजर

फरीदाबाद में किसानों का फूटा गुस्सा, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पुलिस से धक्का-मुक्की

फरीदाबाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शुक्रवार फरीदाबाद दौरे के दौरान बड़ौली और प्रह्लादपुर गांव के किसानों का आक्रोश एक बार फिर सडक़ पर उतर आया। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के नीचे उस वक्त माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया, जब भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष धनसिंह कोतवाल, धरना अध्यक्ष वीरपाल गुर्जर और उनके समर्थक मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने जा रहे थे। विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए तैनात पुलिस और सीआईए के जवानों के साथ किसानों की तीखी झड़प और धक्का-मुक्की हुई, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती बरतते हुए किसानों को वापस लौटाया। धरना अध्यक्ष वीरपाल गुर्जर ने बताया कि बड़ौली और प्रह्लादपुर गांव के किसानों का धरना पिछले 334 दिनों से लगातार जारी है। उनका कहना है कि करीब 16 वर्ष पहले उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसके लिए मात्र 645 रूपये प्रति गज की दर से मुआवजा तय किया गया था। आज के समय में आसमान छूती बाजार दरों को देखते हुए किसान इस पुराने मुआवजे को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। किसानों ने लैंड पूलिंग योजना के तहत समाधान की मांग करते हुए अधिग्रहित जमीन के बदले उचित जमीन उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि अधिग्रहित जमीन पर उनके स्वामित्व वाले 500 से अधिक पुराने मकान बने हुए हैं। किसान इन मकानों को अधिग्रहण के दायरे से पूरी तरह बाहर रखने और जमीन पर उनका मालिकाना हक बरकरार रखने की मांग पर अड़े हुए हैं।

कलसाड़ा फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी समेत तीन गिरफ्तार, किशोर भी शामिल

पलवल। हथीन क्षेत्र के कलसाड़ा गांव में युवक पर देसी कट्टे से फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के मामले में सीआईए पलवल की टीम ने शुक्रवार को एक किशोर सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई पल्सर बाइक बरामद की है। हथियार और कारतूस बरामद करने के लिए मुख्य आरोपी मनोज उर्फ मन्नू और नरेंद्र को एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। पूछताछ पूरी होने के बाद आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, घटना 13 अक्टूबर की शाम करीब 6:30 बजे कलसाड़ा गांव में हुई थी। यहां मोहित पर देसी कट्टे से फायरिंग की गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल की मां लज्जा देवी की शिकायत पर हथीन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने पहले गढ़ी पट्टी, होडल निवासी धर्मेंद्र उर्फ गफू को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीआईए पलवल की टीम ने कार्रवाई करते हुए गढ़ी पट्टी, होडल के पास से मुख्य आरोपी मनोज उर्फ मन्नू और नरेंद्र को गिरफ्तार किया। इस मामले में एक किशोर को भी पकड़ा गया है। सीआईए पलवल प्रभारी नरेंद्र कुमार ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल की गई पल्सर बाइक बरामद कर ली है। मामले में प्रयुक्त देसी कट्टा और कारतूस बरामद करने के लिए मनोज और नरेंद्र को एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था। पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

एमएसएमई हो रहा तबाह, प्राइवेट कंपनी को दिया बिजली लाइसेंस रद्द करो सरकार : अशोक बुवानीवाला

गुरुग्राम। हरियाणा में बिजली वितरण के निजीकरण के खिलाफ 40 हजार बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की हड़ताल से उद्योग-व्यापार चौपट होने लगा है। इसे लेकर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस औद्योगिक प्रकोष्ठ के चेयरमैन अशोक बुवानीवाला ने कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर निजी कंपनी को दिया गया समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस तुरंत रद्द करने की मांग की है। अशोक बुवानीवाला ने कहा कि सरकार के एक गलत फैसले ने पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अंधेरे में धकेल दिया है। हड़ताल के कारण बिजली सप्लाई चरमराई हुई है। फैक्ट्रियों में मशीनें बंद हैं, प्रोडक्शन ठप है और व्यापारी ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा खामियाजा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) भुगत रहे हैं। छोटे उद्यमी पहले ही महंगाई, पूंजी की कमी और बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे हैं, अब बिजली संकट ने उनकी कमर तोड़ दी है। बिजली न होने पर भी उन्हें मजदूरों की तनख्वाह, फैक्ट्री का किराया, बैंक लोन की ईएमआई और दूसरे खर्चे तो देने ही पड़ रहे हैं। इससे हजारों श्रमिकों की आजीविका पर भी संकट मंडरा रहा है।

अशोक बुवानीवाला ने कहा कि सरकार को हठधर्मिता छोड़कर कर्मचारियों से बात करनी चाहिए। टकराव से नहीं, संवाद और सहमति से ही समाधान निकलेगा। उन्होंने सरकार से दो मांगें हैं। पहली तो निजी कंपनी को दिया गया समानांतर वितरण लाइसेंस तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। दूसरी मांग हड़ताली कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से तुरंत वार्ता कर हड़ताल खत्म कराई जाए और बिजली सप्लाई सामान्य की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन को करोड़ों रुपये का नुकसान होगा और हरियाणा से निवेश भी पलायन कर सकता है।

बिजली निजीकरण के विरोध में हड़ताल से ब्लैकआउट

गुरुग्राम,एजेंसी। बिजली वितरण निजी हाथों में सौंपने के विरोध में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के चलते बिजली किल्लत के करंट से हाहाकार मचा है। अनेक इलाकों में पीने के पानी की कमी हो गई। बिजली पर निर्भर खाने की वस्तुएं भी नहीं मिल पा रहीं। उद्योगों में उत्पादन भी प्रभावित हो गया है। हर कोई बिजली कर्मियों की हड़ताल खत्म होने के इंतजार में है। साथ ही सरकार को भी लोग कोस रहे हैं। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के चलते प्रभावित हुई बिजली व्यवस्था से कई इलाके ब्लैक आउट हो चुके हैं। घरों और बाजारों में बिजली नहीं होने से काम भी प्रभावित रहा।

बुधवार रात 10 बजे से शुरू हुई हड़ताल गुरुवार, शुक्रवार को जारी रही। साथ ही बिजली का संकट भी बना रहा। हालात इतने बिगड़े कि गुस्साए लोगों ने बसई चौक व दौलताबाद फ्लाईओवर पर जाम लगा दिया, लेकिन फिर भी बिजली बहाल नहीं हुई। लोगों ने सवाल किए गए जब हड़ताल पहले से घोषित थी तो प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की। बिजली न होने से जलापूर्ति ठप हो गई। सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना तक मुश्किल हो गया। पानी न होने से बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा सके। पानी की किल्लत के कारण घरों में और सार्वजनिक शौचालयों में परेशानी खड़ी हो गई। रोजमर्रा के काम ठप हैं और लोग रात-रात भर बिजली का इंतजार कर रहे हैं। बिजली किल्लत से उद्योग धंधे भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।

सेक्टर-37, बसई, कादीपुर, उद्योग विहार और बेगमपुर खटौला की हजारों उद्योगों में उत्पादन बंद हो गया है। रोजाना करोड़ों का नुकसान इन उद्योगों को हो रहा है। मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट है। पीएफटीआई के चेयरमैन दीपक मैनी के मुताबिक प्रशासन को पहले ही उद्यमियों से संवाद करना चाहिए था। अगर बिजली नहीं दे सकते थे तो तीन दिन फैक्ट्री बंद रखने की सलाह पहले दे देते। पूरे दिन मैनपावर बैठी रही, नुकसान झेलना पड़ा।

बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधा देना प्रशासन की जिम्मेदारी थी, जिसमें वह नाकाम रहा। मुख्यमंत्री को भी पीएफटीआई की ओर से पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी दी गई है। बिजली कर्मचारियों ने शुक्रवार को महरौली रोड स्थित हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने गुरुग्राम और नूंह जिले में पैरलल लाइसेंस देने के विरोध में जुलूस निकाला। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिजली के निजीकरण के फैसले को तुरंत रद्द करने की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि यह सिर्फ बिजली निगम और कर्मचारियों के साथ ही नहीं आम जनता के साथ भी सरकार का धोखा है।

झगड़े की रंजिश के चलते की थी घर पर फायरिंग, दोनों आरोपित गिरफ्तार

फरीदाबाद। दो दिन पूर्व नंगला एनक्लेव पार्ट-2 में स्थित एक घर पर फायरिंग करने के मामले में अपराध शाखा एवीटीएस सिकरोना की टीम ने शुक्रवार को दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान हर्ष उर्फ भूरा (22) और रंजित उर्फ चिन्ना (19), निवासी उत्तम नगर पार्ट-2, नंगला गाजीपुर, फरीदाबाद के रूप में हुई है।

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान एसीपी क्राइम अमन यादव ने बताया कि 21/22 अक्टूबर को देर रात नंगला एनक्लेव पार्ट 2 में सुभाष चौक के पास शिकायतकर्ता सरजीत के घर पर हत्या के प्रयास के नियत से तीन फायर किये गए थे। शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए थाना सारन में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। उन्होंने आगे बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराध शाखाओं की टीम को निर्देशित किया गया। एवीटीएस सिकरोना की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपित आपस में दोस्त हैं। वर्ष 2025 में रंजित उर्फ चिन्ना का झगड़ा हुआ था। शिकायतकर्ता के बेटे सचिन ने झगड़े का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। रंजित ने वीडियो हटाने के लिए कहा, लेकिन सचिन ने वीडियो डिलीट नहीं किया। इसी बात को लेकर वह रंजिश रखने लगा था। जिसके चलते 22 अक्टूबर की रात दोनों आरोपितों ने शिकायतकर्ता के घर पर फायरिंग की थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपित हर्ष उर्फ भूरा और रंजित उर्फ चिन्ना के खिलाफ पहले भी हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है।

कामकाजी महिला हॉस्टल पर ताला लगाने के आदेश दुर्भाग्यपूर्णः पंकज डावर

गुरुग्राम। महिलाओं को सम्मान देने, आगे बढ़ाने का दिखावा करने वाली बीजेपी सरकार के शासन में कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए कामकाजी महिला हॉस्टल बंद किए जा रहे हैं। गरीब घरों की महिलाएं यहां कम खर्च में रहकर अपनी आजीविका कमाती थीं, लेकिन अब उनका यह सपना भी टूटने जा रहा है। इस हॉस्टल को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं, जो महिलाओं के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं। पंकज डावर ने कहा कि वर्ष 1984 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही यह हॉस्टल बनाया गया था। वर्ष 2021 में इस हॉस्टल की बिल्डिंग की जांच की गई और वर्ष 2023 में इसे कंडम घोषित किया गया। इसके बाद एक निजी कंपनी को यह हॉस्टल जिला रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से टेंडर पर दे दिया। अब उस टेंडर को भी खत्म करने के आदेश दिए गए हैं। डावर ने कहा कि जिस बिल्डिंग को कंडम घोषित किया गया था तो उसे फिर से रिपेयरिंग करके टेंडर क्यों दिया गया। जिला रेडक्रॉस सोसायटी ने यह टेंडर दिया। इसके प्रधान जिला उपायुक्त होते हैं। उनके संज्ञान में लाए बिना तो यह टेंडर दिया नहीं गया होगा। ऐसे में उपायुक्त को भी यह देखना चाहिए था कि जो बिल्डिंग कंडम घोषित की जा चुकी है तो उसमें महिलाओं को रखकर उनकी जान को खतरे में क्यों डाला जा रहा। लेकिन नहीं, प्रशासन की ओर से सभी बातों को दरकिनार करके इसे एक निजी फर्म को दे दिया गया।

पंकज डावर ने कहा कि इस हॉस्टल का एक साल पहले के.वी. एंटरप्राइजेज को टेंडर दिया गया था, जो अब रद्द किया गया है। इसका नोटिस निकाल दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि 28 अक्टूबर 2026 को प्रशासन द्वारा कामकाजी महिला आवास को पूर्ण रूप से बंद कर ताला लगा दिया जाएगा। इसलिए महिलाओं को आदेश दिए जाते हैं कि 15 दिन में कामकाजी महिला को खाली करने की कृपा करें। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करते हुए यहां रहने वाली महिलाओं को किसी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाना चाहिए। जब तक नया हॉस्टल ना बने, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार की ओर से पूर्व में इसे नया हॉस्टल बनाने और सेक्टर-10 में एक दूसरा हॉस्टल बनाने की घोषणा की जा चुकी है। लेकिन अभी तक ये दोनों घोषणाएं ठंडे बस्ते में हैं। इन पर कोई काम नहीं हो पाया है। महिलाओं को सुविधाएं देने के दावे करने वाली भाजपा सरकार में कामकाजी महिला हॉस्टल को खाली करवाना भी महिलाओं के लिए परेशानी का कारण बन रहा है।

सूरजकुंड दिवाली मेले से स्वदेशी उत्पादों और कारीगरों को मिल रहा नया बाजारः नायब सिंह सैनी

अशोक कुमार, सद्भावना टुडे

फरीदाबाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सूरजकुंड दिवाली मेला आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के संकल्प को साकार करने वाले श्रम साधकों, कारीगरों और कलाकारों को नया बाजार उपलब्ध करवाने का एक सार्थक प्रयास है। इस मेले का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बिना किसी बिचौलिये के सीधे ग्राहकों तक पहुंचाना और कारीगरों को उनके परिश्रम का उचित लाभ दिलाना है।

उन्होंने कहा कि जब स्थानीय उत्पादों पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा, तो कारीगरों को नए ग्राहक मिलेंगे और उनके काम को आगे बढ़ाने का उत्साह भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री सैनी शुक्रवार को फरीदाबाद स्थित सूरजकुंड में दिवाली मेले के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर पर्यटन एवं विरासत मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। समारोह में कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। नायब सिंह सैनी ने कहा कि 23 से 26 अक्टूबर तक आयोजित यह मेला भारतीय हस्तशिल्प, लोक संस्कृति और विभिन्न क्षेत्रों के खानपान की

विविधता को प्रदर्शित करेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और 'वोकल फॉर लोकल' को जनभागीदारी से जोडऩा आवश्यक है। इसमें गांव के कुम्हार, बुनकर, बढ़ई, छोटे दुकानदार और महिला उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सूरजकुंड का दिवाली मेला इसी भागीदारी को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि दीपावली की सबसे सुंदर रोशनी वह है, जो हमारे घर के साथ-साथ किसी मेहनतकश परिवार के घर को भी रोशन करे। त्योहारों पर स्थानीय कारीगरों के बनाए उत्पाद खरीदने से उनके परिवारों की आजीविका को सहारा मिलता है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम बनकर उभरे हैं। इन समूहों के उत्पाद प्रदेशभर में अपनी पहचान बना रहे हैं। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अब तक 67641 स्वयं सहायता समूहों से 6 लाख से अधिक परिवारों को जोड़ा जा चुका है। इन समूहों को रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश निधि के रूप में सरल ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है। अब तक 596 करोड़ रुपये की विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। सामुदायिक निवेश निधि की राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपये कर दिया गया है। हरियाणा के पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि आज सूरजकुंड धार्मिक आस्था के केंद्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है। इस वर्ष सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का 20 लाख लोगों ने आनंद लिया जिनमें 50 देशों के पर्यटक भी शामिल थे। इसी तर्ज पर सूरजकुंड दीवाली मेला भी धीरे-धीरे लोगों के दिलों में वही जगह बना रहा है। उन्होंने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लोगों से आह्वान किया कि वे अगले 4 दिन तक यहां लगाई गई 300 दुकानों के माध्यम से दिवाली की खरीददारी करें और मेले का आनंद लें।

गुरुग्रामः प्रदूषण से बचाव को मानेसर नगर निगम सड़कों पर करवा रहा ट्रीटेड पानी का छिड़काव

गुरुग्राम। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप-1) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम मानेसर ने लगातार धरातल पर काम करने का दावा किया है। कहा गया है कि निगम क्षेत्र में सड़कों के किनारे जमा धूल मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है।

पानी छिड़काव के लिए वाटर स्प्रिंकलर, ट्रक माउंटेड एंटी स्मॉग गन मशीनों, ट्रेक्टर माउंटेड मशीनों और पानी के टैंकरों की मदद ली जा रही है। निगम की टीम सड़कों पर धूल उड़ने की समस्या को कम करके वायु प्रदूषण नियंत्रण करने का काम कर रही है। नगर निगम की ओर से फिलहाल पांच ट्रक माउंटेड एंटी स्मॉग गन मशीनों, दो ट्रेक्टर माउंटेड मशीन और नौ पानी के टैंकरों के माध्यम से पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। इन संसाधनों की मदद से निगम क्षेत्र की सडक़ों पर ट्रीटेड पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा सोमवार से नौ अतिरिक्त ट्रक माउंटेड एंटी स्मॉग गन मशीनों को निगम के बेड़े में शामिल किया जाएगा। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार ने बताया कि निगम क्षेत्र में ग्रेप के नियमों को सख्ती से

लागू किया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और सडक़ों पर ट्रीटेड पानी के छिड़काव का कार्य लगातार जारी है। इसके अलावा संयुक्त आयुक्त ने कहा कि निगम क्षेत्र में खुले में कूड़े डालने वालों, कूड़े में आग लगाने वाले लोगों पर कार्रवाई के लिए निगम कि ओर से विशेष टीमों का गठन किया गया है। ऐसा करते पकड़े जाने पर दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के चलते 24 घंटे से अधिक समय से बिजली गुल

नूंह। गुरुग्राम और नूंह जिले में बिजली वितरण के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। गुरुवार से शुरू हुई हड़ताल के चलते नूंह जिले में बिजली आपूर्ति बाधित होने से शुक्रवार को भी आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। जिले में 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बावजूद बिजली संकट से लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। ऐसे में लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिजली आपूर्ति ठप होने से एटीएम, साइबर कैफे, दूध की डेयरियों सहित बिजली पर निर्भर अन्य व्यवसायों का कामकाज प्रभावित हुआ है। बिजली के अभाव में कई जगहों पर लोगों को अपने दैनिक कार्य निपटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कारोबारियों के सामने भी कामकाज जारी रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। बिजली संकट लंबा खिंचने से अब लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करने की आशंका भी सताने लगी है।

टाइगर श्रॉफ पर हमले का विरोध करने वाले भीम सेना प्रमुख को मिली धमकी

गुरुग्राम। भीम सेना और संविधान सुरक्षा पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सतपाल तंवर को जान से मारने की धमकी मिली है। सतपाल तंवर ने लॉरेंस बिश्नोई और गोगी गैंग पर यह धमकी देने का आरोप लगाया है। एक महीने के भीतर गुरुग्राम में ही सामने से गोली मारकर हत्या करने की बात कही गई है। सतपाल तंवर की ओर से सेक्टर-37 पुलिस थाना में शिकायत दी गई है। सतपाल तंवर की ओर से शिवानी तंवर द्वारा दी गई शिकायत में कहा गया कि 22 अक्टूबर 2026 को दोपहर करीब 2:59 बजे से लेकर रात तक सतपाल तंवर के आधिकारिक मोबाइल नंबर और फेसबुक पेज पर लगातार धमकियां भेजी गईं।

अज्ञात बदमाशों ने व्हाट्सएप और की फेसबुक मैसेंजर के जरिए धमकी भरे संदेश और कई वॉयस कॉल भेजीं जोकि रिसीव नहीं की गईं। धमकी देने वालों ने संदेश में लॉरेंस ग्रुप, गोगी ग्रुप और केसी ब्रदर ग्रुप का नाम लेते हुए लिखा कि सतपाल तंवर ने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में गलत बोला है, जिसकी सजा सिर्फ मौत है। शिकायत में कहा गया है कि सतपाल तंवर को यह धमकी मुंबई के जुहू में टाइगर श्रॉफ पर हमले का विरोध करने के बाद मिली है। अपने बयान में तंवर में सलमान खान को बड़ा भाई और टाइगर श्रॉफ को छोटा भाई बताया था और लॉरेंस बिश्नोई की आपराधिक गतिविधियों का विरोध किया था।

धमकी के संदेश में यह भी कहा गया कि तुझे इसी महीने के अंदर गोली मारूंगा...तू गुरुग्राम, हरियाणा में रहता है ना, तुझे वहीं मारूंगा, इंतजार कर तू। सतपाल तंवर ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके लिखा कि-मौत जिसकी महबूबा हो उसे मरने से डर नहीं लगता। भीम सेना ने थाना सेक्टर-37 गुरुग्राम के एसएचओ और पुलिस कमिश्नर को औपचारिक शिकायत भेजकर तुरंत एफआईआर दर्ज करने, आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने तथा सतपाल तंवर की सुरक्षा पुख्ता करने की मांग की है। थाना सेक्टर-37 प्रभारी इंस्पेक्टर मंजीत ने बताया कि देर रात भीम सेना की तरफ से शिकायत मिली है।

बिजली किल्लत से मची हाहाकार, सड़कों पर उतरे लोग, जाम से परेशान हुई जनता

फरीदाबाद। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का व्यापक असर शहर के अलग-अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। एनआईटी-2, टीटू कॉलोनी, पल्ला और सारण में करीब 24 घंटे से ज्यादा समय से बिजली आपूर्ति प्रभावित होने के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को पीने के पानी के लिए लाइनों में लगना पड़ रहा है। वहीं, रात के समय बच्चों को मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ रही है। परेशान होकर लोगों ने गुरुवार देर रात सडक़ों पर उतरकर जाम लगा दिया।

फरीदाबाद के सारन चौक पर गुरुवार की रात लोगों ने जाम लगा दिया, यह जाम शुक्रवार दोपहर तक जारी रहा, दोपहर बाद थक हारकर लोगों ने स्वयं ही जाम खोल दिया। इसके अलावा सेक्टर-10 स्थित भाजपा विधायक मूलचंद शर्मा के कार्यालय के बाहर बिजली से परेशान लोगों ने जाम लगा दिया। इस दौरान पार्षद दीपक चौधरी भी लोगों के साथ मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि बिजली की लंबी कटौती से घरेलू कामकाज, पानी की आपूर्ति और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अब देखना होगा कि बिजली निगम इन इलाकों में बिजली कब तक बहाल कर पाता है और लोगों को पानी की समस्या से कब राहत मिलती है। वहीं शहर के अन्य हिस्सों में भी बिजली की किल्लत का व्यापक असर देखने को मिला, बैंकों, कार्यालयों तथा ऑफिसों में लोगों के काम प्रभावित हुए।

लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियां पेश आई। इसके अलावा जगह-जगह लगे जाम के चलते शहर में यातायात व्यवस्था कछुआ चाल से चलती नजर आई, लोगों को मिनटों का सफर करने के लिए घण्टों का सामना करना पड़ा। बिजली संकट से परेशान लोग सेक्टर-64 स्थित बिजली पावर हाउस भी पहुंचे और विभाग के कर्मचारियों के प्रति नाराजगी जताई। हरियाणा में कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। 24 अक्तूबर तक कर्मचारियों की ये हड़ताल चलेगी। कर्मचारी गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को 25 साल के लिए बिजली वितरण का लाइसेंस देने के फैसले का विरोध कर रहे हैं।

सात हजार रिश्वत लेती जीएसटी इंस्पेक्टर रंगे हाथों गिरफ्तार

गुरुग्राम। हरियाणा एसीबी की गुरुग्राम यूनिट ने जीएसटी विभाग की महिला इंस्पेक्टर श्रुति रानी को सात हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इंस्पेक्टर ने एक कारोबारी से जीएसटी नंबर जारी करने के बदले घूस मांगी थी। एसीबी के मुताबिक एक स्थानीय कारोबारी ने अपनी फर्म के लिए नए जीएसटी नंबर के लिए आवेदन किया था। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद इंस्पेक्टर श्रुति रानी ने फाइल रोक रखी थी। जब कारोबारी ने संपर्क किया तो इंस्पेक्टर ने वेरिफिकेशन रिपोर्ट पास करने और सर्टिफिकेट जारी करने के बदले सात हजार रुपये की मांग की।

कारोबारी रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने सीधे/ष्टक्च को लिखित शिकायत दे दी। प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर एक विशेष टीम बनाई गई। एसीबी ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जाल बिछाया। शिकायतकर्ता को केमिकल लगे सात हजार रुपये देकर इंस्पेक्टर के पास भेजा गया। जैसे ही कारोबारी ने पैसे दिए और इशारा किया, टीम ने धावा बोलकर इंस्पेक्टर को दबोच लिया। हाथ धुलवाने पर पानी का रंग गुलाबी हो गया, जो रिश्वत का वैज्ञानिक सबूत है। मौके से पूरी रकम

बरामद कर ली गई। आरोपी को हिरासत में लेकर एसीबी थाने लाया गया है। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एसीबी अधिकारियों का कहना है कि इंस्पेक्टर को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। जांच की जाएगी कि क्या इस खेल में विभाग के अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं और अन्य लंबित फाइलों की भी जांच होगी।

सपा की सियासत में आजम की ताकत और रामपुर जेल का सियासी फलसफा

अशोक भाटिया

उत्तर प्रदेश की राजनीति में रामपुर की जेल सिर्फ एक चारदीवारी नहीं, बल्कि वर्तमान में समाजवादी पार्टी के भविष्य और मुस्लिम सियासत के नए ध्रुवीकरण का केंद्र बन चुकी है। 22 अक्टूबर 2026 को सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पार्टी के सबसे कद्दावर मुस्लिम चेहरे आजम खान के बीच रामपुर जिला जेल में हुई लगभग एक घंटे की मुलाकात केवल दो नेताओं की शिष्टाचार भेंट नहीं थी। यह उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात पर चली गई एक ऐसी चाल है, जिसके दूरगामी परिणाम न केवल समाजवादी पार्टी के भीतर, बल्कि पूरे राज्य के सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने पर दिखाई देंगे। कानूनी शिकंजे में फंसे और चुनावी राजनीति से तकनीकी रूप से दूर हो चुके आजम खान की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके एक इशारे पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दर्जनों सीटों का गणित बदल सकता है। यही कारण है कि अखिलेश यादव को खुद रामपुर जेल पहुंचकर यह संदेश देना पड़ा कि समाजवादी पार्टी में आजम खान की हैसियत न तो कम हुई है और न ही उन्हें हाशिए पर धकेला जा सकता है। यह मुलाकात इस बात का जीवंत प्रमाण है कि सत्ता और कानूनी मुकदमों के उतार-चढ़ाव के बावजूद, सपा की सियासत में आजम की ताकत का सूरज पूरी तरह अस्त नहीं हुआ है, बल्कि रामपुर जेल की सलाखों के पीछे से वह एक नई ऊर्जा के साथ उभर रहा है। यह घटनाक्रम यह भी दर्शाता है कि जब-जब उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन या बड़े राजनैतिक उलटफेर की नींव रखी जाती है, तब-तब रामपुर का किला और वहां का नेतृत्व स्वत: ही मुख्यधारा की चर्चा के केंद्र में आ जाता है।

इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए समाजवादी पार्टी के अंतर्विरोधों और उत्तर प्रदेश के बदलते मुस्लिम नेतृत्व के संकट को देखना जरूरी है। पिछले कुछ समय से यह चर्चा आम थी कि आजम खान के जेल जाने और उनके परिवार पर आए कानूनी संकट के दौरान समाजवादी पार्टी ने उस आक्रामकता के साथ उनका साथ नहीं दिया, जिसकी उम्मीद एक संस्थापक सदस्य को होती है। पार्टी के भीतर और बाहर इस बात को लेकर सुगबुगाहट थी कि अखिलेश यादव अपनी छवि को एक नए, आधुनिक और गैर-विवादास्पद रूप में ढालने के लिए 'माई' (मुस्लिम-यादव) समीकरण से थोड़ा इतर 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का नारा दे रहे हैं। इस नए विमर्श में आजम खान जैसे पुराने समाजवादी दिग्गजों की कट्टर छवि फिट नहीं बैठ रही थी। इसी बीच, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और अन्य क्षेत्रीय दलों ने इस खालीपन को भरने की कोशिश शुरू कर दी। ओवैसी लगातार यह आरोप लगाते रहे कि सपा मुस्लिमों के वोट तो लेती है, लेकिन जब उनके बड़े नेताओं पर संकट आता है, तो नेतृत्व चुप्पी साध लेता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कभी आजम खान का अभेद्य किला माना जाता था, वहां मुस्लिम मतदाताओं के बीच उपजे इस असमंजस को अखिलेश यादव भांप चुके थे। रामपुर लोकसभा उपचुनाव और उसके बाद के घटनाक्रमों में जिस तरह से अंदरूनी गुटबाजी सामने आई, उसने पार्टी आलाकमान को सचेत कर दिया कि आजम खान को नजरअंदाज करने की कीमत 2027 में बेहद भारी पड़ सकती है। इसलिए, अखिलेश यादव का रामपुर जेल जाना राजनीतिक मजबूरी भी था और एक सोची-समझी रणनीति भी, जिसके जरिए उन्होंने एक ही झटके में ओवैसी के नैरेटिव को ध्वस्त करने और अपने कोर वोटर को यह भरोसा दिलाने का प्रयास किया कि 'नेताजी' (मुलायम सिंह यादव) के दौर के स्तंभ आज भी उतने ही आदरणीय हैं। यह कदम यह भी स्पष्ट करता है कि सपा अपने पारंपरिक और वफादार वोट बैंक को किसी भी अन्य वैचारिक प्रयोग की वेदी पर होम करने के लिए तैयार नहीं है। जेल की इस मुलाकात ने न केवल सपा के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा है, बल्कि पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान पर भी एक तरह से विराम लगाने का काम किया है। हाल के दिनों में रामपुर के वर्तमान सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और आजम खान के समर्थकों के बीच की दूरी जगजाहिर रही है। स्थानीय स्तर पर संगठन दो धड़ों में बंटा नजर आ रहा था। अखिलेश यादव ने जेल से बाहर आकर जिस तरह 'आजम थे, आजम हैं और आजम रहेंगे' का हुंकार भरा, उससे उन्होंने यह साफ कर दिया कि रामपुर और पूरे रूहेलखंड क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का चेहरा और कमान आज भी परोक्ष रूप से आजम खान के पास ही रहेगी।

खबरों के मुताबिक, इस मुलाकात के दौरान आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा ने अखिलेश यादव को संभावित उम्मीदवारों और रणनीतिक बदलावों की एक सूची भी सौंपी। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि 2027 के विधानसभा चुनावों में टिकटों के बंटवारे से लेकर गठबंधन के स्वरूप तक, आजम खान की राय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। भले ही आजम खान खुद चुनावी मैदान में न उतर सकें, लेकिन उनका 'रिमोट कंट्रोल' यूपी की सियासत में बेहद प्रभावी रहने वाला है। उनका यही प्रभाव अखिलेश यादव को उनके पास खींच लाया, क्योंकि वे जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज में आजम खान की आवाज आज भी एक भावनात्मक अपील रखती है, जिसे कोई दूसरा नेता रिप्लेस नहीं कर पाया है। यह प्रभाव केवल रामपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि मुरादाबाद, बिजनौर, बरेली और अमरोहा जैसे पूरे मुस्लिम बहुल बेल्ट में आजम खान की राजनीतिक छत्रछाया आज भी टिकटार्थियों के भाग्य का फैसला करने की क्षमता रखती है। दूसरी तरफ, इस मुलाकात ने विपक्षी खेमे, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर सपा पर हमलावर होने का मौका दे दिया है। भाजपा ने इसे 'तुष्टिकरण की राजनीति का नया अध्याय' और 'अपराधियों को संरक्षण देने की कोशिश' करार दिया है। सत्ताधारी दल का तर्क है कि कानून सम्मत कार्रवाई के तहत जेल में बंद एक सजायाफ्ता नेता से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की यह मुलाकात यह दर्शाती है कि सपा आज भी अपने पुराने ढर्रे और तुष्टिकरण की नीति से बाहर नहीं निकल पाई है। भाजपा के रणनीतिकार इस मुलाकात को बहुसंख्यक मतदाताओं के बीच भुनाने की कोशिश करेंगे, ताकि सपा के खिलाफ एक बार फिर ध्रुवीकरण का माहौल बनाया जा सके। भाजपा के लिए यह मुलाकात एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए वे यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव का 'पीडीए' सिर्फ एक मुखौटा है, और असलियत में वे उसी पुरानी राजनीति की ओर लौट रहे हैं जिसे जनता ने नकारा था। सुभासपा और अन्य छोटे दलों ने भी इसे केवल एक 'चुनावी नौटंकी' बताया है। विपक्ष का यह तीखा हमला दिखाता है कि वे भी अच्छी तरह जानते हैं कि आजम और अखिलेश का यह पुनर्मिलन अगर जमीन पर रंग लाया, तो विपक्षी दलों के लिए मुस्लिम वोटों में सेंध लगाना नामुमकिन हो जाएगा। भाजपा की ओर से आने वाले तीखे बयान इस बात का भी संकेत हैं कि वे आने वाले समय में कानून-व्यवस्था के मुद्दे को एक बार फिर चुनाव के केंद्र में लाएंगे और आजम खान का नाम लेकर सपा को घेरने की हरसंभव कोशिश करेंगे।

इस पूरे परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या रामपुर जेल की यह मुलाकात समाजवादी पार्टी को 2027 की सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा पाएगी? उत्तर प्रदेश की सियासत अब 2012 या 2017 जैसी नहीं रह गई है। मतदाता बेहद जागरूक हैं और केवल भावनात्मक अपीलों पर वोट नहीं करते। आजम खान की ताकत का एक पहलू अगर उनका भारी जनसमर्थन है, तो दूसरा पहलू उनकी छवि को लेकर होने वाला काउंटर-ध्रुवीकरण भी है। अखिलेश यादव के सामने चुनौती यह होगी कि वे आजम खान की ताकत का इस्तेमाल मुस्लिम वोटों को एकजुट करने में तो करें, लेकिन इसके साथ ही बहुसंख्यक और गैर-यादव ओबीसी मतदाताओं को छिटकने न दें। पीडीए का जो गुलदस्ता अखिलेश ने तैयार किया है, उसमें आजम खान की हिस्सेदारी को इस तरह पिरोना होगा कि वह समावेशी दिखे, न कि केवल एक वर्ग विशेष की राजनीति। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो जाट-मुस्लिम-दलित गठबंधन सपा बनाने का प्रयास कर रही है, उसमें आजम खान की स्वीकार्यता को संतुलित रखना एक बेहद बारीक राजनीतिक कला होगी। यदि सपा इस संतुलन को साधने में सफल रही, तो रामपुर जेल से शुरू हुआ यह सफर 2027 में लखनऊ के सचिवालय तक पहुंच सकता है, अन्यथा ध्रुवीकरण की तेज हवा इस पूरी रणनीति को बिखेर भी सकती है। बहरहाल, रामपुर जेल के बंद कमरों से निकला यह सियासी संदेश उत्तर प्रदेश की वादियों में गूंजने लगा है। इसने यह तय कर दिया है कि आने वाले दिनों में रामपुर की धरती एक बार फिर सूबे की राजनीति का कुरुक्षेत्र बनेगी। आजम खान जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी सपा की सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक बने हुए हैं, और अखिलेश यादव के इस कदम ने यह साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता आज भी रामपुर के सियासी गलियारों से होकर ही गुजरता है।

> भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे सकारात्मक बात यह है कि एमएसएमई सेक्टर में लगातार अच्छा काम हो रहा है तो दूसरी और सर्विस सेक्टर में तो एक तरह से लगातार उछाल आ रहा है। कच्चे तेल के भावों में तो जैसे आग ही लग रही है और उपलब्धता को लेकर भी लाख झंझट के बावजूद इकोनोमी को बूस्टअप रखने में खास बाधा नहीं आ रही है। देसी-विदेशी निवेश में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। महंगाई के बावजूद बाजार में मांग बरकरार है। बाजार में मांग से साफ है कि लोगों की क्रय शक्ति बनी हुई है। सर्विस सेक्टर में टूरिज्म, बैंकिंग, आईटी, और इसी तरह के अन्य क्षेत्र उल्लेखनीय परिणाम दे रहे हैं। नवंबर में दीपावली के त्यौहार के चलते बाजार और अधिक गतिशील हो जाएगा क्योंकि दीपावली पर बाजार में तेजी आती ही आती है। जानकारों की मानें तो नवंबर माह में दीपावली पर 7 लाख करोड़ का कारोबार अनुमानित किया जा रहा है। यह पिछली दीपावली की तुलना में 15 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक अधिक रहने की संभावना है। इसी तरह से सेवा क्षेत्र में भी अच्छी ग्रोथ जारी रहने का अनुमान है। इसके अलावा विपरीत हालातों के बावजूद निर्यात में लगातार बढ़ोतरी जारी है। देश की इकोनोमिक ग्रोथ के कारण देसी-विदेशी निवेश के बेहतर हालात दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि चाहे आईएमएफ हो या मूडीज, ओईसीडी हो या वर्ल्ड बैंक, एशियन डब्लपमेंट बैंक या एसएण्डपी या फिच सभी ने भारत की इकोनोमी की ग्रोथ को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं।

आर्थिक मोर्चे पर विकास के सकारात्मक संकेत

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद दुनिया भर की रेटिंग संस्थाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गतिमान स्वीकार करते हुए वैश्विक औसत से लगभग दो गुणी विकास दर रहने की संभावना जताई है। यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वैश्विक परिस्थितियों में कहीं और किसी तरह का सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। ईरान-अमेरिका युद्ध हो या रूस-यूक्रेन युद्ध हो या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के तानाशाही पूर्ण तुगलकी निर्णय हो या कच्चे तेल के भावों में बेतहाशा बढ़ोतरी और हार्मुज का संकट हालात समूचे विश्व में विकट से विकटतर बने हुए हैं। अब तो फ्रांस के हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं तो उसका असर जहां यूरोप में दिखाई देगा वहीं भारत में भी हालात को प्रभावित करने के कतिपय प्रयास जारी है। अच्छी बात यह है कि देश-दुनिया के गंभीर हालातों के बावजूद आर्थिक क्षेत्र की दुनिया की लगभग सभी रेटिंग संस्थाओं ने इंडियन इकोनोमी की ग्रोथ रेट को लेकर आशा से भी अधिक विश्वास जताया है। रेटिंग संस्थाओं की ही मानें तो 2026 की वैश्विक औसत आर्थिक विकास दर 3 दशमलव 1 फीसदी रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है वहीं, दुनिया की रेटिंग संस्थाओं ने भारत के आर्थिक परिणामों को देखते हुए जुलाई की तुलना में अक्टूबर आते-आते ग्रोथ को 6 दशमलव 9 से लेकर 7 दशमलव 1 रहने की उम्मीद जताई है। खास बात यह है कि विश्व रेटिंग संस्थाओं में से किसी भी संस्था ने जुलाई की रेटिंग की तुलना में नकारात्मक ग्रोथ नहीं दिखा कर ग्रोथ रेट में इजाफा ही जाहिर किया है।

दरअसल, देश में मांग और आपूर्ति से लेकर निर्यात तक में लगातार विकास देखा जा रहा है। देश में मांग और आपूर्ति की बेहतर हालात है तो निर्यात में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। यह भी तब जब वैश्विक मांग कमजोर देखी जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे सकारात्मक बात यह है कि एमएसएमई सेक्टर में लगातार अच्छा काम हो रहा है तो दूसरी और सर्विस सेक्टर में तो एक तरह से लगातार उछाल आ रहा है। कच्चे तेल के भावों में तो जैसे आग ही लग रही है और उपलब्धता को लेकर भी लाख झंझट के बावजूद इकोनोमी को बूस्टअप रखने में खास बाधा नहीं आ रही है। देसी-विदेशी निवेश में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। महंगाई के बावजूद बाजार में मांग बरकरार है। बाजार में मांग से साफ है कि लोगों की क्रय शक्ति बनी हुई है। सर्विस सेक्टर में टूरिज्म, बैंकिंग, आईटी, और इसी तरह के अन्य क्षेत्र उल्लेखनीय परिणाम दे रहे हैं। नवंबर में दीपावली के त्यौहार के चलते बाजार और अधिक गतिशील हो जाएगा क्योंकि दीपावली पर बाजार में तेजी आती ही आती है। जानकारों की मानें तो नवंबर माह में दीपावली पर 7 लाख करोड़ का कारोबार अनुमानित किया जा रहा है। यह पिछली दीपावली की तुलना में 15 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक अधिक रहने की संभावना है। इसी तरह से सेवा क्षेत्र में भी अच्छी ग्रोथ जारी रहने का अनुमान है। इसके अलावा विपरीत हालातों के बावजूद निर्यात में लगातार बढ़ोतरी जारी है। देश की इकोनोमिक ग्रोथ के कारण देसी-विदेशी निवेश के बेहतर हालात दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि चाहे आईएमएफ हो या मूडीज, ओईसीडी हो या वर्ल्ड बैंक, एशियन डब्लपमेंट बैंक या एसएण्डपी या फिच सभी ने भारत की इकोनोमी की ग्रोथ को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। भारत का आरबीआई का आकलन तो पहले ही सबके सामने हैं। एकमात्र फिच रेटिंग संस्था ऐसी है जिसने इंडियन इकोनोमी की ग्रोथ रेट 6.9 प्रतिशत आंकी जो फिच की ही पूर्व की रेटिंग 6.5 प्रतिशत से ही अधिक है। मूडीज सहित कुछ रेटिंग संस्थाओं ने जहां अब 7 प्रतिशत विकास दर आंक रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक, ओईसीडी आदि संस्थाओं को भरोसा है कि भारत की आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत से अधिक यानी की 7.1 प्रतिशत रहने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नित नए निर्णयों से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे असर, युद्ध और तनाव के हालातों में सुधार नहीं होने, हार्मुज जैसी समस्या का समाधान नहीं होने, वैश्विक राजनीतिक अस्थिरता के दौर के बावजूद एक ही सधी हुई नीति का परिणाम है कि देश की अर्थव्यवस्था विकास की गति को ना केवल बनाए हुए हैं अपितु उसकी विकास का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके लिए समग्र और समन्वित प्रयासों को श्रेय जाता है। जहां घरेलू मांग में कमी नहीं आई है, वहीं निवेश का बेहतर माहौल बना हुआ है। एमएसएमई को उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना का लाभ सीधे इकोनोमी का मिल रहा है वहीं रणनीतिक क्षेत्रों सेमी कण्डक्टर, डिफेंस, इलेक्ट्रोनिक्स, आईटी आदि आदि क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है। यही कारण है कि आज इंडियन इकोनोमी और उसकी ग्रोथ पर वैश्विक रेटिंग संस्थाएं अपना विश्वास व्यक्त कर रही है।

विचार

कॉकरोच जनता पार्टी: सियासी बुलबुला या सैलाब

राधा रमण

भारतीय लोकतंत्र में सियासी पार्टियों का बनना-बिगड़ना कोई नई बात नहीं है। हर चुनाव से पहले कुछ नई पार्टियां, कुछ नए चेहरे, कुछ नए नारे और कुछ नए झंडे सामने आते रहे हैं। उनमें से कुछ को हम गंभीरता से लेते हैं और कुछ को कोस कर भूल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेरोजगारों से संबंधित एक टिप्पणी में 'कॉकरोच' शब्द से निकली सोशल मीडिया की पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) वैसी ही एक पार्टी है। हालांकि उसके संयोजक अमेरिका रिटर्न महाराष्ट्र के संभाजीनगर निवासी अभिजीत दीपके यह दावा करते हैं कि सीजेपी चुनावी राजनीति से दूर रहनेवाली एक प्रेशर ग्रुप है। लेकिन सीजेपी के पदाधिकारियों के ख्वाब बड़े हैं। नीट पेपरलीक मामले में केन्द्रीय शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफा दे देने के बाद तो उनकी महत्वाकांक्षा और भी कुलांचे मारने लगी है। मोदी सरकार के कार्यकाल में यह पहला मौका था, जब सरकार को मांगें माननी पड़ी वरना पिछले 12 वर्षों से तो लोगबाग केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की पूर्व में कही बात को ही सच मान बैठे थे कि यह अलग मिजाज की सरकार है, यहां इस्तीफा नहीं होता है। देश ने देखा कि चाहे विवाद में फंसने पर तत्कालीन राज्यमंत्री कौशल किशोर का मामला हो, बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह का, अजय मिश्र टेनी का अथवा हरदीप सिंह पुरी का, विपक्ष के चौतरफा दबाव के बावजूद सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। किसी का इस्तीफा नहीं हुआ लेकिन सीजेपी के एक धरने ने सरकार को सोचने के लिए विवश कर दिया। कॉकरोच नाम भले ही मजाकिया लगे पर इसके पीछे का गुस्सा और अनुभव बहुत गहरा है। कॉकरोच का स्वभाव क्या है? वह अंधेरे में रहता है, गंदगी में पनपता है, रोशनी पड़ते ही भागता है, मारो तो और तेजी से फैलता है। सबसे बड़ी बात- उसकी प्रजाति कभी खत्म नहीं होती। यही दावा अभिजीत दीपके भी करते हैं। सीजेपी का आगाज अच्छा रहा लेकिन अंजाम दिशाहीन हो गया लगता है। शिक्षामंत्री पद से धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके और उनकी टीम के नेता अपने को बिना चुनावी राजनीति में उलझे सुपर सरकार मानने लगे। विपक्षी पार्टियां भी मन से, बेमन से उनके पीछे-पीछे चलने लगीं। कारण यह कि विपक्ष सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की हालत में नहीं रह गया। वहां कार्यकर्ता कम नेता अधिक हो गए हैं। सीजेपी को यह स्पेस अच्छा दिखा। उसके नेता देशभर के स्कूलों की दशा सुधारने के लिए कई राज्यों में घूमने लगे।

राजस्थान में तो पिटे भी, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में विरोध झेला। लेकिन उसके पहले झारखंड में छात्रों के आंदोलन से दूरी बना ली। पंजाब के स्कूलों की बेहतरी की बात करने लगे। इससे संदेह गहराया। पड़ताल में पता चला कि सीजेपी के पूरे नेतृत्व का पूर्व में आम आदमी पार्टी से जुड़ाव रहा है। इससे सरकार को उन्हें घेरने का बढ़िया मौका मिल गया। उधर, गाहे बगाहे सीजेपी के लोग अदालतों के खिलाफ भी बेवजह की टिप्पणी करने लगे। इससे भी लोगों का मोहभंग हुआ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले सवा साल से चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे लेकिन उन्हें विपक्षी दलों का भी भरपूर समर्थन नहीं मिलता था। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भले कुछ दिन राहुल के साथ चले लेकिन बाद के दिनों में चुनाव में टिकट बांटने और प्रचार कार्य में लगे रहे। उन्हें उम्मीद थी कि वह अकेले ही सरकार बना लेंगे। यही स्थिति पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की थी। महाराष्ट्र में शरद पवार और संजय राउत सिर्फ एक्स पर बयान देकर अपना कर्तव्य निभा गए। दक्षिण और पूर्वोत्तर में भी यही हालात थे। अखबार में खबर छपने के बाद और चुनावों में बुरी तरह हार जाने के बाद विपक्ष गोलबंद हुआ। ऐसे में सीजेपी के नेताओं को लगा कि बहती गंगा में हाथ धो लें तो विपक्ष के सिरमौर हो जाएंगे। उधर, पहले से तैयार सरकार कॉकरोचों को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार बैठी थी। 10 अक्टूबर को अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन रिहा किया तो शांति बनाए रखने की शर्तों के साथ बेल बांड भरवाकर छोड़ा। यही कारण है कि 14 अक्टूबर को दोबारा जंतर-मंतर पर गिरफ्तार होने के बाद सौरभ दास और आशुतोष रांका को जेल से जमानत मिलने में हफ्तेभर से ज्यादा समय लग गया। सीजेपी के एक और रणनीतिकार अकिंज्य शिंदे भी शर्तों के साथ बेल बांड भरकर ही बाहर आए हैं। इससे कॉकरोच जनता पार्टी के सामने कई मुश्किलें दिख रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने उन्हें जेन जी मानने से इनकार कर दिया है। शर्तों के अनुसार आगे की आंदोलन के लिए उन्हें पुलिस की अनुमति लेनी होगी। पुलिस अनुमति देगी तो नए शर्तों के साथ देगी। शर्तों को तोड़ा तो फिर जेल जाना होगा। ऐसे में कानूनी बेड़ियों के साथ अब उनके लिए आंदोलन की राह और कठिन हो गई है। इन सबके बीच बड़ा सवाल यह कि कॉकरोच जनता पार्टी की कोशिशें बुलबुला बनकर रह जाएंगी अथवा सड़कों पर अराजकता फैलाकर देश के लोकतांत्रिक स्वरूप को अस्थिरता की बाढ़ में डुबो देंगी।

एक नजर

लूटकांड का चार घंटे में उद्भेदन, एक आरोपित गिरफ्तार

बक्सर,एजेंसी। जिले के नया भोजपुर थाना क्षेत्र में भैंसहा पुल के पास हुई लूट की घटना का पुलिस ने महज चार घंटे के भीतर उद्भेदन कर एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपित के ठिकाने से लूटे गए 80 पेटी कुकुरे भी बरामद किए हैं। घटना में शामिल अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने बताया कि 23 अक्टूबर को सूचना मिली कि भैंसहा पुल के पास तीन अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने एक पिकअप वाहन से लूट की घटना को अंजाम दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डुमरांव के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया। टीम ने सूचना का सत्यापन करने के बाद तकनीकी अनुसंधान और छापेमारी के जरिए घटना में शामिल अपराधियों की पहचान करने का प्रयास किया। इसी क्रम में ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले अंजू कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उसने लूट की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने लूटे गए 80 पेटी कुरकुरे बरामद कर लिए। इस मामले में नया भोजपुर थाना कांड संख्या 111/26, दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। छापेमारी दल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भास्कर रंजन, अंचल निरीक्षक अरविंद कुमार सहित नया भोजपुर थाना की पुलिस और अन्य जवान शामिल थे।

अभिनेत्री काजल राघवानी ने बेतिया में किया ऐश्प्रा जेम्स का उद्घाटन

बेतिया। बेतिया शहर के सुप्रिया रोड मुख्य पथ पर ऐश्प्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स के पहले शोरूम का भव्य शुभारंभ हुआ। भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी की मौजूदगी में पश्चिम चंपारण के सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने फीता काटकर शोरूम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एमएलसी सौरभ कुमार, विधायक नारायण शाह, पूर्व विधायक उमाकांत सिंह, पूर्व विधायक राघव शरण पांडेय, पूर्व विधायक प्रकाश राय, भाजपा नेता राहुल कुमार तथा प्रमुख शंभू तिवारी सहित कई जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और व्यवसायी मौजूद रहे। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। अभिनेत्री काजल राघवानी ने कहा कि आभूषण भारतीय परंपरा, संस्कृति और व्यक्तिगत स्टाइल का खूबसूरत संगम हैं। बेतिया में खुले इस शोरूम में ग्राहकों को उनकी पसंद और बजट के अनुरूप पारंपरिक, ब्राइडल और आधुनिक डिजाइन के आभूषण मिलेंगे। कंपनी के डायरेक्टर अनूप सराफ ने बताया कि वर्ष 1940 से ग्राहकों का विश्वास उनकी सबसे बड़ी पूंजी रहा है। इसी भरोसे के साथ कंपनी ने वर्ष 2028 तक बिहार के विभिन्न शहरों में 30 शोरूम खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बेतिया के फ्रेंचाइजी ओनर विवेक कनोडिया ने कहा कि उनका प्रयास ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण आभूषणों के साथ भरोसेमंद खरीदारी का बेहतर अनुभव उपलब्ध कराना है। शोरूम के शुभारंभ को लेकर शहर में उत्साह का माहौल रहा।

सारण शिक्षक निर्वाचन में पश्चिम चंपारण में 88.65% मतदान

बेतिया। बिहार विधान परिषद के 03–सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए शुक्रवार को पश्चिम चंपारण जिले में मतदान शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष माहौल में संपन्न हुआ। जिले के सभी 18 प्रखंड मुख्यालयों में बनाए गए मतदान केंद्रों पर कुल 1701 मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना था। इनमें से 1508 मतदाताओं ने मतदान किया। इस प्रकार जिले में कुल 88.65 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। मतदान करने वालों में 1283 पुरुष और 225 महिला मतदाता शामिल रहीं। स्वच्छ, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप सभी मतदान केंद्रों पर स्टेटिक फोर्स के साथ दंडाधिकारियों की तैनाती की गई थी। इसके अलावा मतदान प्रक्रिया पर सतत निगरानी रखने के लिए जोनल अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जिलाधिकारी तरनजोत सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदान व्यवस्था और प्रक्रिया का जायजा लिया। वहीं, जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित कर जिलेभर के मतदान केंद्रों से पल–पल की जानकारी प्राप्त की जा रही थी। प्रशासनिक मुस्तैदी, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम और अधिकारियों की सतत निगरानी के बीच जिले में मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई।

डॉ हेडगेवार जी के जीवन, त्याग, अनुशासन एवं राष्ट्र निर्माण के विचारधारा को जन–जन तक पहुंचाएगी राज्य सरकार : मुख्यमंत्री

पटना में आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर महानाट्य 'युगप्रवर्तक डॉ. हेडगेवार' का मंचन, सीएम सम्राट चौधरी ने किया शुभारंभ

पटना,एजेंसी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार देर शाम सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र परिसर स्थित बापू सभागार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी वर्ष के अवसर पर नादब्रह्म संस्था, नागपुर द्वारा निर्मित भव्य महानाट्य 'संघ सृजन का आविष्कार : युगप्रवर्तक डॉ हेडगेवार' के मंचन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हेडगेवार जी के जीवन, त्याग, अनुशासन एवं राष्ट्र निर्माण के विचारधारा को जन–जन तक पहुंचाएगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए ऐतिहासिक है। डॉ हेडगेवार जी के जीवन पर आधारित इस महानाट्य के माध्यम से राष्ट्रभक्ति, त्याग, अनुशासन और समाज सेवा जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि डॉ हेडगेवार जी एक स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और कुशल संगठनकर्ता थे, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि डॉ हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कर संगठन और राष्ट्रसेवा की एक ऐसी परंपरा विकसित की, जो आगे चलकर देशभर में विस्तारित हुई। संघ की शाखाओं के माध्यम से इससे जुड़े लोग राष्ट्रसेवा, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रसार के लिए निरंतर कार्य करते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत को समृद्ध, उन्नत और विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि

डॉ हेडगेवार जी के जीवन, संघर्ष, विचारों और संकल्प को समझने के लिए यह महानाट्य एक महत्वपूर्ण माध्यम है। बिहार में दो करोड़ से अधिक युवा हैं। नई पीढ़ी, विशेषकर जेन–जी को डॉ हेडगेवार जी के जीवन, राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण और उनके विचारों से अवगत कराना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महानाट्य का मंचन केवल पटना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिहार के अन्य जिलों में भी इसका आयोजन किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक युवा इससे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डॉ0 हेडगेवार जी के जीवन और विचारों से लोगों को परिचित कराने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इस अवसर पर महानाट्य के निर्माता पद्माकर धानोरकर ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम को कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ प्रमोद कुमार तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बिहार–झारखंड के क्षेत्रीय कार्यवाह डॉ मोहन सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रगान की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव, पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू, पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय कार्यवाह डॉ मोहन सिंह, बिहार भाजपा संगठन महामंत्री भिखूभाई दलसानिया, महानाट्य के निर्माता पद्माकर धानोरकर, कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार, पटना मेडिकल कॉलेज एवं एवं अस्पताल के अधीक्षक डॉ राजीव कुमार सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

विक्रमशिला सेतु पर युद्धस्तर पर पुनर्स्थापन कार्य जारी, दिसंबर तक स्थायी स्टील ट्रस ब्रिज से बहाल होगी आवाजाही

भागलपुर। उत्तर और दक्षिण बिहार के साथ–साथ सीमांचल को जोड़ने वाले ऐतिहासिक विक्रमशिला सेतु पर इन दिनों कायाकल्प का काम बेहद तेजी से चल रहा है। मई महीने में स्लैब क्षतिग्रस्त होने के बाद वैकल्पिक रूप से लगाए गए अस्थायी बेली ब्रिज को सितंबर के अंत में पूरी तरह हटा दिया गया है और अब 1 अक्टूबर से आगामी 3 महीनों के लिए पुल पर हर प्रकार के वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। पथ निर्माण निगम और विशेषज्ञ एजेंसियों की टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं ताकि तय समय सीमा तक पुल को पूरी तरह सुरक्षित बनाकर दोबारा खोला जा सके। बिहार कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 126.26 करोड़ रुपये के भारी–भरकम बजट से इस बार पुल की स्थायी मरम्मत की जा रही है। मरम्मत कार्य को बेहद आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। महाराष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसी 'मैटे एसोसिएट्स' द्वारा चिन्हित कमजोर और क्षतिग्रस्त कंक्रीट स्लैबों को तोड़ने का काम पूरा कर लिया गया है। अब दिल्ली की विख्यात 'मंगलम फर्म' ने पुनर्स्थापन के अगले चरण का खाका खींचा है, जिसके तहत क्षतिग्रस्त हिस्सों पर एक मजबूत और स्थायी 'स्टील ट्रस ब्रिज' का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुल के सुपरस्ट्रक्चर का वजन कम करने के लिए वर्षों पुरानी आरसीसी रेलिंग और फुटपाथ को काटकर हटाया जा रहा है, जिसकी जगह सुहानी प्रोजेक्ट्स द्वारा हल्की और बेहद मजबूत स्टील रेलिंग लगाई जाएगी। इस बार प्रशासन केवल मरम्मत ही नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा को लेकर भी बेहद गंभीर है। पहली बार पुराने विक्रमशिला सेतु पर आधुनिक 'ब्रिज हेल्थ मॉनीटरिंग सिस्टम' लगाने का बड़ा फैसला लिया गया है। यह डिजिटल सिस्टम चौबीसों घंटे पुल की संरचनात्मक स्थिति और किसी भी संभावित खतरे (जैसे दरारें या झुकाव) पर बारीकी से नजर रखेगा। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर यह सिस्टम प्रशासन को समय से पहले ही डिजिटल अलर्ट भेज देगा, जिससे भविष्य में बड़े हादसों को रोका जा सकेगा। वहीं सड़क मार्ग पूरी तरह ठप होने के कारण जिला प्रशासन द्वारा बियाडा, बाबूपुर और जाह्नवी चौक घाटों के बीच आम लोगों की सुविधा के लिए 12 जहाजों और रो–रो वेसल्स के माध्यम से मुफ्त स्टीमर सेवा संचालित की जा रही है। मोटरसाइकिल और आम यात्री इसी जलमार्ग के सहारे गंगा पार कर रहे हैं।

एसडीपीओ ने किया वासुदेवा में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा

बक्सर/डुमरांव। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने वासुदेवा थाना क्षेत्र के बिंद टोली गांव में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। प्रेस वार्ता के माध्यम से इसकी जानकारी देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भास्कर रंजन ने शुक्रवार को बताया कि फर्नीचर बनाने की आड़ में अवैध हथियार तैयार करने का धंधा किया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी करते हुए दो अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया। वहीं उनकी निशानदेही पर दो देसी कट्टा, एक एकनाली बंदूक, एक अर्धनिर्मित देसी कट्टा, छह कारतूस समेत हथियार बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले कई उपकरण बरामद किए गए। घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि 22 अक्टूबर को गुप्त सूचना मिली थी कि वासुदेवा थाना क्षेत्र के वासुदेवा बिंद टोली निवासी बिगन बिंद अपने घर से अवैध हथियारों का कारोबार कर रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। इस टीम में अंचल निरीक्षक अरविंद कुमार, डीआईयू प्रभारी सुधीर कुमार, वासुदेवा थानाध्यक्ष अनिल कुमार पासवान, डीआईयू बक्सर की टीम तथा वासुदेवा थाना के सशस्त्र बल शामिल थे।टीम ने सूचना का सत्यापन करते हुए संबंधित ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान बिगन बिंद और उक्त कार्यों में संलिप्त नावानगर थाना क्षेत्र के निवासी संतोष शर्मा को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान अर्द्धनिर्मित हथियारों व उपकरण के अलावा पुलिस ने 22 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। वहीं हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामानों में छोटे–बड़े छेनी के 26 टुकड़े, लोहे के बने 20 छोटे–बड़े उपकरण, दो अर्धनिर्मित बैरल, दो ट्रीमर, दो हैमर, देसी कट्टे का एक हिस्सा, सेंटर पंच, लोहे का मारकट, चार प्लास, आठ सरसी, लोहे काटने वाली एक कैंची, लोहे के तीन छोटे–बड़े पाइप, दो रेती, एक हथौड़ी, एक रेमर, लोहे की निहाई, गुनिया, जमुरा और एक बांच शामिल है। इसके अतिरिक्त एक पुरानी ग्रेडर मशीन, हवा देने वाली एक भट्ठी और छोटे–बड़े 13 स्प्रिंग भी जब्त किए गए। इस मामले में वासुदेवा थाना कांड संख्या 125/26, दिनांक 22 अक्टूबर 2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

कटिहार रेलवे स्टेशन पर 'मखाना जंक्शन' का शुभारंभ, स्थानीय किसानों को मिलेगा बड़ा बाजार

कटिहार,एजेंसी। जिले के प्रसिद्ध मखाना उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुक्रवार को कटिहार रेलवे स्टेशन पर 'मखाना जंक्शन' स्टॉल का शुभारंभ किया गया। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की 'एक स्टेशन, एक उत्पाद' योजना के अंतर्गत स्थापित इस स्टॉल का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी एवं मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। जिला प्रशासन एवं जिला कृषि विभाग की इस संयुक्त पहल से स्टेशन से गुजरने वाले देश भर के यात्रियों को अब कटिहार का मखाना और उससे बने प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे।

इस अवसर पर जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि यह पहल स्वस्थ खानपान, स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन तथा किसान समृद्धि के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है। रेलवे स्टेशन जैसे व्यस्त सार्वजनिक स्थल पर स्टॉल खुलने से स्थानीय कृषि उत्पादों के विपणन को मजबूती मिलेगी और जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति प्राप्त होगी। रेलवे स्टेशन स्थित 'मखाना जंक्शन' स्टॉल पर यात्रियों के लिए रोस्टेड (भुना) मखाना, पेरी–पेरी मखाना, चीज एवं चटपटा मखाना, कैरेमल मखाना सहित पारंपरिक मखाना बर्फी, मखाना ठेकुआ, मखाना लड्डू और खीर मिक्स जैसे विभिन्न प्रकार के मूल्य संवर्धित उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि विभाग की प्राथमिकता जिले के विशिष्ट कृषि उत्पादों को सीधा बाजार मुहैया कराना है, ताकि बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो और मखाना उत्पादक किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। इस आउटलेट के शुरू होने से जिले में मखाना प्रसंस्करण, पैकेजिंग और स्थानीय उद्यमिता से जुड़े युवाओं व स्वयं सहायता समूहों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

'एक स्टेशन, एक उत्पाद' योजना के तहत डीएम और डीआरएम ने संयुक्त रूप से किया उद्घाटन; यात्रियों को मिलेंगे मखाना से बने लजीज व पौष्टिक व्यंजन

सारण शिक्षक निर्वाचन में सभी 20 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न, 86.85% हुआ मतदान

सारण। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सारण जिले के सभी 20 मतदान केंद्रों पर आज कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से मतदान संपन्न हो गया। मतदान प्रक्रिया पूर्वाह्न 8 बजे से प्रारंभ होकर अपराह्न 4 बजे तक शांतिपूर्ण माहौल में चली। मतदान समाप्ति के पश्चात संकलित अंतिम आंकड़ों के अनुसार, जिले में कुल 86.85 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। इसमें पुरुष मतदाताओं की भागीदारी 87.98 प्रतिशत और महिला मतदाताओं की भागीदारी 82.68 प्रतिशत रही।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व चुनावी प्रेक्षक दीपक आनंद एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने विभिन्न मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर पूरी मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्रों पर उपलब्ध व्यवस्थाओं, सुरक्षा प्रबंधों तथा प्रशासनिक तैयारियों का बारीकी से अवलोकन किया। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने हेतु सुपर जोनल एवं जोनल दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों तथा त्वरित कार्रवाई दल द्वारा लगातार कड़ी निगरानी रखी गई। विभिन्न प्रखंडों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पानापुर में सर्वाधिक 100 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। इसके अलावा बनियापुर में 96.86%, तरैया में 96.67%, लहलादपुर में 96.08%, अमनौर में 94.70%, परसा में 93.59%,

मकेर एवं सोनपुर में 92.42%, मढ़ौरा में 92.16%, नगरा में 91.59%, दरियापुर में 89.95%, दिघवारा व इसुआपुर में 88.41%, मांझी में 87.50%, रिविलगंज में 86.72%, एकमा में 84.91% तथा मसरख में 84.51 प्रतिशत मतदान रिकॉर्ड किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंडों में सघन वाहन जांच किया गया। मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद निर्धारित नियमों एवं पारदर्शिता के तहत सभी अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मतपेटियों को सील किया गया। इसके पश्चात, मतदान दलों, जोनल दंडाधिकारियों एवं पुलिस बल की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी मतपेटियों को सुरक्षित रूप से निर्धारित बज्रगृह के लिए रवाना कर दिया गया।

बिहार के 9 जिलों के बाढ़ प्रभावित किसानों को मिलेगा फसल क्षति अनुदान, 25 तक करें आवेदन

पटना,एजेंसी। बिहार सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत दी है। सरकार ने बाढ़ में किसानों को हुई क्षति के लिए अनुदान देने का निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य के नौ जिलों की 289 पंचायतों के बाढ़ प्रभावित किसानों को फसल क्षति अनुदान दिया जायेगा। इसके लिए किसानों को आवेदन करना होगा। किसान 25 अक्टूबर तक अनुदान के लिए आवेदन कर सकेंगे। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के अनुसार बिहार सरकार बाढ़ से प्रभावित किसानों को फसल क्षति की भरपाई के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। सितंबर 2026 के अंतिम सप्ताह में नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण आई बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। राज्य के 9 जिलों के 43 प्रखंडों की 289 चिह्नित पंचायतों के पात्र किसान 25 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई कर प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। कृषि इनपुट अनुदान योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे फसल क्षति से उत्पन्न कठिनाइयों से उबर सकें और आगामी कृषि कार्यों को सुचारु रूप से जारी रख सकें। उन्होंने पात्र किसानों से निर्धारित समय–सीमा के भीतर आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की। विजय सिन्हा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के किसान कल्याण, आत्मनिर्भर भारत और समृद्ध कृषि का संकल्प डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में किसानों के हितों की रक्षा और उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट अनुदान उपलब्ध कराना इसी प्रतिबद्धता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार का उद्देश्य फसल क्षति से प्रभावित किसानों को समय पर आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें पुनः कृषि कार्यों के लिए सक्षम बनाना, कृषि उत्पादन को निरंतर बनाए रखना तथा किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है।

कृषि मंत्री ने बताया कि कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत फसल क्षति के लिए अलग–अलग दरों पर सहायता राशि निर्धारित की गई है। वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित क्षेत्र के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा शाश्वत एवं बहुवर्षीय फसलों, जिनमें गन्ना भी शामिल है, के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत अधिकतम दो हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अनुदान देय होगा। न्यूनतम सहायता राशि असिंचित क्षेत्र के लिए 1,000 रुपये, सिंचित क्षेत्र के लिए 2,000 रुपये तथा शाश्वत एवं बहुवर्षीय फसलों के लिए 2,500 रुपये निर्धारित की गई है। दरभंगा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, सारण, कटिहार और पटना जिले के चिह्नित प्रखंडों एवं पंचायतों के बाढ़ प्रभावित पात्र किसान इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। प्रभावित प्रखंडों और पंचायतों की सूची डीबीटी कृषि पोर्टल पर उपलब्ध है। योजना का लाभ पात्र पंजीकृत रैयत एवं गैर–रैयत किसानों को दिया जाएगा।

एक नजर

एशियाई पैरा खेलों में भारत ने झटके रिकॉर्ड 114 पदक, तालिका में चौथे स्थान पर

नई दिल्ली। एशियाई पैरा खेल-2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 114 पदकों के साथ अपने अभियान का समापन किया है। भारत ने 30 स्वर्ण, 34 रजत और 49 कांस्य पदक अपने नाम किए। इस तरह भारतीय दल ने कुल पदकों की संख्या के मामले में पिछले संस्करण के प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया। भारत ने शुक्रवार को 9 स्वर्ण सहित कुल 26 पदक जीतकर अपने अभियान का समापन किया, हालांकि, इन खेलों का आधिकारिक समापन 24 अक्टूबर दिन शनिवार को भव्य समापन समारोह के साथ किया जाएगा।

भारत ने पिछले रिकॉर्ड को छोड़ा पीछे

वर्ष 2023 के पिछले संस्करण में भारत ने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य सहित कुल 111 पदक जीते थे। इस बार भारत ने कुल पदकों की संख्या में दो पदकों का सुधार किया। पिछले संस्करण की तुलना में भारत ने एक अधिक स्वर्ण और तीन अधिक रजत पदक जीते, जबकि कांस्य पदकों की संख्या दो कम रही। भारतीय खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन ने पैरा खेलों में देश की बढ़ती मजबूती को रेखांकित किया है। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, निशानेबाजी और तैराकी सहित विभिन्न स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया।

चीन पदक तालिका में शीर्ष पर

चीन पदक तालिका में 427 पदक (204 स्वर्ण, 115 रजत और 108 कांस्य) के साथ शीर्ष पर है, जबकि जापान 185 पदक (63 स्वर्ण, 60 रजत और 62 कांस्य) के साथ दूसरे और उज्बेकिस्तान 145 पदक (45 स्वर्ण, 49 रजत और 51 कांस्य) के साथ तीसरे स्थान पर है।

अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट : सेकंड राउंड में पहुंचे अविनाश, शौर्य, राजकुमार, अक्षय, चारू

मुरादाबाद। मुरादाबाद टेनिस एसोसिएशन के तत्वावधान में एचएस चड्ढा मेमोरियल एमटी-400 चैंपियंस कप अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दिन शुक्रवार को अविनाश कुंवर, चारू दत्त, शौर्य ने अपने मुकाबले जीतकर सेकेंड राउंड में जगह बनाई। अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में देशभर से 225 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कांठ रोड स्थित ब्रायससिटी जिमखाना में आज दूसरे दिन शुरू हुई प्रतियोगिता में समर्थ सिंह को भी विकास के खिलाफ वॉकओवर मिला। इसके बाद अविनाश कुंवर ने अतुल को 6-0, 6-1 से शिकस्त दी। चारू दत्त ने अनंत राणा को 6-0, 6-0 से हराया, जबकि शौर्य वर्मा ने संचित गांधी को 6-1, 10-4 से पराजित किया। राजकुमार ने तेजस्वी को 6-1, 10-3 से मात दी। वहीं, अक्षय आहूजा ने अक्षय पंजाबी को 6-0, 6-1 से हराकर जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में पुणे, मुंबई, मेरठ, गुरुग्राम, रुद्रपुर, लुधियाना और लखनऊ समेत विभिन्न शहरों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। 22 से 28 अक्टूबर तक होने वाले टूर्नामेंट में 30 से 75 वर्ष आयु वर्ग के पुरुष और महिला खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करेंगे। विश्व टेनिस संघ के ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता का आयोजन चड्ढा ग्रुप की ओर से सरदार गुरजीत सिंह चड्ढा के नेतृत्व में उनके दिवंगत पिता सरदार हरभजन सिंह चड्ढा की स्मृति में प्रतिवर्ष किया जाता है। टूर्नामेंट के दौरान गुरजीत सिंह चड्ढा, डॉ. संजय गुप्ता, डॉ. अनंत राणा, डॉ. अनुराग अग्रवाल, अवनीश, मनु, शाकिब और डॉ. रितेश आदि मौजूद रहे।

भारतीय महिला क्रिकेटर सब्बिनेनी मेघना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शीर्ष क्रम की बल्लेबाज सब्बिनेनी मेघना ने शुक्रवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। आंध्र प्रदेश में जन्मीं मेघना घरेलू क्रिकेट में रेलवे का प्रतिनिधित्व करती थीं। उन्होंने वर्ष 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। उन्होंने भारत की ओर से तीन एकदिवसीय और 17 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले। मेघना 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम का भी हिस्सा थीं। हालांकि, इसके बाद वह भारतीय टी20 टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर सकीं और बाद के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के आयोजनों में भी उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला।

मेघना ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'पहली बार हाथ में बल्ला लेकर मैदान पर उतरना और विश्व मंच पर देश की जर्सी पहनना मेरे लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं था। एक खिलाड़ी के रूप में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करते हुए मेरा हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ है। मैदान मेरा दूसरा घर रहा है। इसने मुझे धैर्य और विनम्रता सिखाई तथा ऐसी यादें और दोस्तियां दीं, जिन्हें मैं जीवनभर अपने साथ रखूंगी। मेरे परिवार का धन्यवाद, जो हर अच्छे-बुरे दौर में मेरे साथ खड़ा रहा और जिसने मेरे लिए अनगिनत त्याग किए। मेरे प्रशिक्षकों, साथी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ का भी आभार, जिन्होंने मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित किया और जिनके साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने का अवसर मिला। प्रशंसकों का भी धन्यवाद, जिनकी तालियों और उत्साह ने हर कदम पर मुझे ऊर्जा दी। उन्होंने आगे लिखा, 'मैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, आंध्र क्रिकेट संघ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात जायंट्स और रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूं। मेरे पूरे करियर के दौरान उनके निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद। मुझे सर्वोच्च स्तर पर अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए मंच और अवसर देने के लिए मैं उनकी आभारी हूं। भले ही एक खिलाड़ी के रूप में मेरा सफर समाप्त हो रहा है, लेकिन क्रिकेट के साथ मेरा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। मैं हमेशा इस खेल से गहराई से जुड़ी रहूंगी। मेरा इरादा अपना जीवन खेल को कुछ लौटाने, अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देने और उस खेल की सेवा करने के लिए समर्पित करना है, जिसने मुझे सब कुछ दिया। धन्यवाद, क्रिकेट। तुम हमेशा मेरे दिल, मेरे जुनून और जीवनभर के उद्देश्य बने रहोगे।' महिला प्रीमियर लीग के पहले सत्र में मेघना को गुजरात जायंट्स ने अपनी टीम में शामिल किया था। वर्ष 2024 में वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जुड़ीं और उसी वर्ष खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा बनीं।

प्रतीका के शतक और श्री चरणी की घातक गेंदबाजी से भारत ने जिम्बाब्वे को नौ विकेट से हराया

वडोदरा, एजेंसी। प्रतीका रावल के नाबाद शतक और श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में जिम्बाब्वे को नौ विकेट से करारी शिकस्त दी। भारत ने 198 रन के लक्ष्य को केवल 27.1 ओवर में एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने तीन मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली। प्रतीका रावल ने 96 गेंदों पर नाबाद 100 रन की शानदार पारी खेली। वहीं, शेफाली वर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों पर नाबाद 64 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान छक्कों की झड़ी लगाकर भारतीय टीम को आसान जीत दिलाई। स्मृति मंधाना ने भी 32 रन का योगदान दिया।

इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे की पारी को 49.5 ओवर में 197 रन पर समेट दिया। श्री चरणी ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 23 रन देकर चार विकेट झटके, जबकि क्रांति गौड़ ने 42 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। जिम्बाब्वे की ओर से बिलव्ड बिजा ने सर्वाधिक 62 रन बनाए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम को तीसरे ओवर में पहला झटका लगा, जब क्रांति गौड़ ने लोरिन फिरी को अपनी ही गेंद पर शानदार कैच लेकर पवेलियन भेजा। हालांकि, शुरुआती ओवरों में भारतीय क्षेत्ररक्षकों ने कुछ आसान मौके गंवाए। ऋचा घोष ने चिपो मुगेरी-तिरिपानो का कैच छोड़ा, जबकि पदार्पण कर रहीं जिंतमणि कलिता की गेंद पर दीप्ति शर्मा ने मोडेस्टर मुपाचिक्वा का कैच टपका दिया। इसके बाद श्री चरणी ने मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने पहले मेडन ओवर डाला और फिर मुगेरी-तिरिपानो को

पगबाधा आउट किया। चरणी ने मुपाचिक्वा को भी पवेलियन भेजा। दीप्ति शर्मा ने शार्न मेयर्स को कैच आउट कराकर जिम्बाब्वे का स्कोर 70 रन पर चार विकेट कर दिया।

मुश्किल में फंसी जिम्बाब्वे की पारी को बिजा ने संभाला। उन्होंने न्याशा ग्वांजुरा के साथ पांचवें विकेट के लिए 43 रन जोड़े और अपना अर्धशतक पूरा किया। मिशेल मावुंगा ने 23 गेंदों पर 29 रन बनाकर टीम को तेजी से रन दिलाने की कोशिश की। हालांकि, श्री चरणी ने कलिता के हाथों उन्हें कैच कराकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। इसके बाद जिम्बाब्वे की पारी लड़खड़ा गई। टीम ने तीन रन के भीतर तीन विकेट गंवा दिए। शेफाली वर्मा ने कप्तान नोमवेलो सिबांडा को पगबाधा आउट किया, जबकि क्रांति गौड़ ने बिजा को मिड ऑफ पर कैच कराया। दीप्ति शर्मा ने पारी की आखिरी गेंद से पहले तेंदई मकुशा को बोल्ड कर जिम्बाब्वे की पारी समाप्त कर दी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। प्रतीका रावल और स्मृति मंधाना ने पहले विकेट के लिए तेजी से रन जोड़े। भारत ने पावरप्ले के बाद 10 ओवर में बिना किसी नुकसान के 72 रन बना लिए थे। प्रतीका ने 54 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्हें 45 रन के निजी स्कोर पर जीवनदान भी मिला। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 94 रन जोड़े, जिसके बाद मंधाना 32 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद शेफाली वर्मा ने तेजी से रन बनाने की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने 26वें ओवर में चार की गेंदों पर तीन छक्के जड़ते हुए 20 रन बटोरे और केवल 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी ओर, प्रतीका ने 27वें ओवर में चौका लगाकर अपना तीसरा एकदिवसीय शतक पूरा किया। प्रतीका और शेफाली ने दूसरे विकेट के लिए केवल 70 गेंदों पर नाबाद 106 रन की साझेदारी कर भारत को 22.5 ओवर शेष रहते शानदार जीत दिला दी। संक्षिप्त स्कोर: जिम्बाब्वे महिला टीम 197 रन (49.5 ओवर; बिलव्ड बिजा 62, श्री चरणी 4/23, क्रांति गौड़ 3/42)। भारत महिला टीम 200/1 (27.1 ओवर; प्रतीका रावल नाबाद 100, शेफाली वर्मा नाबाद 64, स्मृति मंधाना 32)। भारत नौ विकेट से विजयी।

एशियन पैरा खेल : नवदीप सिंह ने भाला फेंक एफ-40/41 वर्ग में जीता कांस्य

आइची-नागोया। भारत के नवदीप सिंह ने एशियाई पैरा खेल-2026 में पैरा एथलेटिक्स की पुरुषों की भाला फेंक एफ-40/41 स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया। नवदीप ने फाइनल में 42.55 मीटर दूर भाला फेंककर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत के ही रवि रोंगाली इसी स्पर्धा में 31.64 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ पांचवें स्थान पर रहे। स्पर्धा में ईरान के सादेघ बेइत ने 45.78 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता। इंडोनेशिया के अंसयारी ने 43.55 मीटर का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। अंसयारी ने अपने छठे प्रयास में 43.55 मीटर की दूरी हासिल की, जो उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा।

नवदीप का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दूसरे प्रयास में आया। उन्होंने दूसरे प्रयास में 42.55 मीटर दूर भाला फेंका। उनका पहला प्रयास अमान्य रहा, जबकि तीसरे प्रयास में उन्होंने 41.28 मीटर की दूरी हासिल की। चौथे, पांचवें और छठे प्रयास में वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सुधारने में सफल नहीं हो सके। इसके बावजूद उनका दूसरा प्रयास उन्हें कांस्य पदक दिलाने के लिए पर्याप्त रहा। ईरान के सादेघ बेइत ने पहले प्रयास में 44.94 मीटर की दूरी हासिल कर अच्छी शुरुआत की। उनका दूसरा प्रयास अमान्य रहा, लेकिन तीसरे प्रयास में उन्होंने 45.78 मीटर दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक की स्थिति मजबूत कर ली। इसके बाद के प्रयासों में वह इस दूरी को पार नहीं कर सके। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 45.78 मीटर रहा। इंडोनेशिया के अंसयारी ने पहले प्रयास में 40.26 मीटर, दूसरे में 42.72 मीटर और तीसरे में 41.11 मीटर की दूरी हासिल की। चौथा प्रयास अमान्य रहने के बाद उन्होंने पांचवें प्रयास में 42.71 मीटर की दूरी हासिल की। इसके बाद छठे और अंतिम प्रयास में 43.55 मीटर दूर भाला फेंककर रजत पदक पक्का किया। भारत के रवि रोंगाली एफ-40 वर्ग में 31.64 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ पांचवें स्थान पर रहे। उन्होंने पहले प्रयास में 31.59 मीटर दूर भाला फेंका। दूसरे प्रयास में उनकी दूरी 27.46 मीटर रही, जबकि तीसरे प्रयास में उन्होंने 30.82 मीटर की दूरी हासिल की। चौथे प्रयास में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 31.64 मीटर की दूरी तय की। पांचवां प्रयास अमान्य रहा और छठे प्रयास में वह 28.73 मीटर तक ही भाला फेंक सके। इराक के अहमद नास ने एफ-40 वर्ग में 35.16 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ चौथा स्थान हासिल किया। उन्होंने पांचवें प्रयास में अपनी सर्वश्रेष्ठ दूरी हासिल की।

एशियन पैरा खेल : प्रणव सूरमा ने क्लब थ्रो में दिलाया भारत को 30वां स्वर्ण, धरमबीर ने जीता कांस्य

आइची-नागोया। एशियाई पैरा खेल-2026 में भारतीय पैरा एथलीट प्रणव सूरमा ने पुरुषों की क्लब थ्रो एफ51 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश को बड़ी सफलता दिलाई। प्रणव ने 32.87 मीटर दूर क्लब फेंककर खेलों का नया रिकॉर्ड बनाया। इसी स्पर्धा में भारत के धरमबीर ने 27.71 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। इस तरह भारत ने स्पर्धा में दो पदक जीते, जबकि एक अन्य भारतीय खिलाड़ी अमित कुमार मामूली अंतर से पदक से चूककर चौथे स्थान पर रहे।

प्रणव सूरमा ने अपने पहले प्रयास में 31.66 मीटर और दूसरे प्रयास में 32.11 मीटर की दूरी हासिल की। तीसरा और चौथा प्रयास अमान्य रहने के बाद उन्होंने पांचवें प्रयास में 31.95 मीटर की दूरी तय की। इसके बाद छठे और अंतिम प्रयास में 32.87 मीटर दूर क्लब फेंककर उन्होंने स्वर्ण पदक के साथ खेलों का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दक्षिण कोरिया के जिवोन जंग ने 28.40 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास पहले दौर में आया। उन्होंने इसके बाद अपने प्रदर्शन में सुधार करने की कोशिश की, लेकिन 28.40 मीटर की दूरी पार नहीं कर सके। भारत के धरमबीर ने 27.71 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने पहले प्रयास में 23.66 मीटर की दूरी तय की। दूसरे और तीसरे प्रयास में वह वैध दूरी दर्ज नहीं कर सके। चौथे प्रयास में उन्होंने 25.89 मीटर और पांचवें प्रयास में 27.71 मीटर की दूरी हासिल की। उनका छठा प्रयास 22.89 मीटर का रहा। पांचवें प्रयास में हासिल की गई दूरी ने उन्हें तीसरा स्थान दिलाया। भारत के ही अमित कुमार 27.26 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ चौथे स्थान पर रहे। अमित ने पहले प्रयास में 22.52 मीटर दूर क्लब फेंका, जबकि दूसरे प्रयास में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 27.26 मीटर की दूरी हासिल की। तीसरे और चौथे प्रयास में उन्होंने क्रमश: 26.27 मीटर और 26.54 मीटर की दूरी तय की। उनके पांचवें और छठे प्रयास अमान्य रहे। वह कांस्य पदक जीतने वाले धरमबीर से 45 सेंटीमीटर पीछे रह गए। प्रणव सूरमा का रिकॉर्ड प्रदर्शन और धरमबीर का कांस्य पदक भारतीय पैरा एथलेटिक्स के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।

41वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मप्र की अर्चिता चौहान ने जीता कांस्य पदक

भोपाल, एजेंसी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुक्रवार से शुरू हुई 41वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में मध्य प्रदेश की एथलीट अर्चिता चौहान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। उन्होंने बालिका अंडर-20 वर्ग की 5000 मीटर दौड़ में 17 मिनट 36.25 सेकंड का समय दर्ज किया और तीसरा स्थान हासिल किया। खेल विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि 23 से 27 अक्टूबर तक आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहले दिन हुई बालिका अंडर-20 वर्ग की 5000 मीटर दौड़ में अर्चिता चौहान ने अपनी गति और सहनशक्ति का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

उन्होंने निर्धारित दूरी 17 मिनट 36.25 सेकंड में पूरी करते हुए कांस्य पदक हासिल किया। लंबी दूरी की दौड़ में खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता, धैर्य और गति पर नियंत्रण महत्वपूर्ण होता है। अर्चिता ने इन सभी पहलुओं का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने की उपलब्धि हासिल की। 41वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप देश के युवा एथलीट्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का महत्वपूर्ण मंच है। इस प्रतियोगिता में अर्चिता चौहान ने पदक जीतकर मध्य प्रदेश में एथलेटिक्स के क्षेत्र में युवा खिलाड़ियों की संभावनाओं को उजागर किया है। राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की उपलब्धियां खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ ही उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती हैं। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण

मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने अर्चिता चौहान को 41वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अर्चिता के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा और मेहनत से प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। खिलाड़ियों की उपलब्धियां प्रदेश के अन्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करती हैं। मंत्री सारंग ने विश्वास जताया कि प्रदेश के खिलाड़ी भविष्य में भी अपनी प्रतिभा और परिश्रम के दम पर नई उपलब्धियां हासिल कर मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करेंगे। खेल मंत्री ने कहा कि चेन्नई में आयोजित 41वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अर्चिता चौहान का कांस्य पदक जीतना मध्य प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बालिका अंडर-20 वर्ग की 5000 मीटर दौड़ में उनके प्रदर्शन ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। उनकी यह सफलता प्रदेश के उभरते एथलीट्स के लिए प्रेरणादायक है।

पीवी. सिंधु फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचीं, अश्मिता चालीहा का संघर्षपूर्ण सफर क्वार्टर फाइनल में थमा

पेरिस। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्रेंच ओपन के महिला एकल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चिउ पिन-चियान को सीधे गेमों में 21-13, 21-14 से हराया। भारत की अश्मिता चालीहा को महिला एकल क्वार्टर फाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा के खिलाफ 21-10, 17-21, 21-16 से हार का सामना करना पड़ा।

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। उन्होंने पहले गेम में चिउ को दबाव में रखते हुए 21-13 से जीत दर्ज की। दूसरे गेम में भी सिंधु ने अपना दबदबा बनाए रखा और मध्यांतर तक 11-2 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली। चिउ ने वापसी की कोशिश की, लेकिन सिंधु ने उन्हें ज्यादा अवसर नहीं दिया और दूसरा गेम 21-14 से जीतकर अंतिम चार में प्रवेश कर लिया। सेमीफाइनल में सिंधु का सामना इंडोनेशिया की पांचवीं वरीयता प्राप्त पुत्री वारदानी और जापान की हिना अकेची के बीच होने वाले मुकाबले की विजेता से होगा। सिंधु ने इससे पहले जापान की रिको गुंजी को 44 मिनट तक चले मुकाबले में 21-12, 21-16 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। इससे पहले उन्हें थाईलैंड की सुपनिदा कातेथोंग के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। सिंधु ने वह

मुकाबला 21-14, 8-21, 23-21 से जीता था। निर्णायक गेम में जीत से केवल दो अंक दूर रहने के बावजूद वह लगातार 11 अंक गंवा बैठी थीं, लेकिन अंत में उन्होंने संयम बनाए रखते हुए जीत हासिल की। दूसरी ओर, भारत की अश्मिता चालीहा ने जापान की अनुभवी खिलाड़ी नोजोमी ओकुहारा के खिलाफ शानदार संघर्ष किया, लेकिन निर्णायक गेम में पिछड़ने के कारण उन्हें हार झेलनी पड़ी। ओकुहारा ने यह मुकाबला 21-10, 17-21, 21-16 से अपने नाम किया।

ओकुहारा ने पहले गेम में 5-1 की बढ़त के साथ अच्छी शुरुआत की और मध्यांतर तक 11-6 से आगे रहीं। जापानी खिलाड़ी ने इसके बाद भी दबाव बनाए रखा और पहला गेम 21-10 से जीत लिया। दूसरे गेम में अश्मिता ने दमदार वापसी की। दोनों खिलाड़ी शुरुआती दौर में 4-4 की बराबरी पर थीं, लेकिन इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने तेजी से शॉट लगाते हुए और नेट पर शानदार खेल दिखाकर मध्यांतर तक 11-5 की बढ़त बना ली। ओकुहारा ने वापसी करते हुए स्कोर 15-15 कर दिया, लेकिन अश्मिता ने महत्वपूर्ण मौकों पर बेहतर खेल दिखाया और 21-17 से गेम जीतकर मुकाबला निर्णायक गेम में पहुंचा दिया। निर्णायक गेम में अश्मिता ने 4-2 की बढ़त के साथ शुरुआत की। हालांकि, ओकुहारा ने वापसी करते हुए 7-4 की बढ़त बना ली। अश्मिता ने हार नहीं मानी और स्कोर 9-9 तथा फिर 12-12 और 14-14 तक बराबर किया। मुकाबले के अंतिम चरण में भारतीय खिलाड़ी की गलतियां बढ़ गईं, जिसका फायदा उठाकर ओकुहारा 20-16 तक पहुंच गईं। उन्होंने पहला ही मैच अंक भुनाकर मुकाबला जीत लिया।

एशियन पैरा खेल : सुमित की अगुवाई में भारत का भाला फेंक में क्लीन स्वीप, तीनों पदक भारतीय खिलाड़ियों के नाम

आइची-नागोया। एशियाई पैरा खेल-2026 में भारतीय पैरा एथलीटों ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीनों पदकों पर कब्जा जमा लिया। सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीतकर अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया, जबकि महेंद्र गुर्जर ने रजत और संदीप संजय सरगर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इस तरह भारत ने एफ42-एफ44 और एफ61-एफ64 वर्गों की संयुक्त स्पर्धा में पहले तीनों स्थान हासिल किए। पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल ने 72.46 मीटर दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में यह दूरी हासिल की और 1,112 रजा अंक अर्जित किए। सुमित ने पहले प्रयास में 70.16 मीटर की दूरी तय की थी। इसके बाद तीसरे प्रयास में 69.79 मीटर, चौथे में 69.18 मीटर और छठे में 68.44 मीटर का प्रदर्शन किया। उनका पांचवां प्रयास अमान्य रहा। दूसरे प्रयास में सिंधु की गई 72.46 मीटर की दूरी उन्हें शीर्ष स्थान पर बनाए रखने के लिए पर्याप्त रही।

महेंद्र गुर्जर ने 59.03 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ रजत पदक जीता। एफ42 वर्ग में उन्होंने खेलों का नया रिकॉर्ड भी बनाया और 1,066 रजा अंक हासिल किए। महेंद्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तीसरे प्रयास में आया। उन्होंने पहले प्रयास में 53.72 मीटर और दूसरे में 54.44 मीटर की दूरी हासिल की थी। तीसरे प्रयास में 59.03 मीटर भाला फेंकने के बाद वह अपनी दूरी में सुधार नहीं कर सके, लेकिन उनका रिकॉर्ड प्रदर्शन उन्हें दूसरा स्थान दिलाने में सफल रहा। संदीप संजय सरगर ने 64.48 मीटर दूर भाला फेंककर कांस्य पदक जीता। एफ44 वर्ग में उन्होंने खेलों का नया रिकॉर्ड बनाया और 1,006 रजा अंक हासिल किए। संदीप ने पहले प्रयास में 62.38 मीटर और दूसरे में 62.69 मीटर की दूरी हासिल की। तीसरे प्रयास में उन्होंने 64.48 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। चौथे प्रयास में उनकी दूरी 60.72 मीटर और पांचवें में 63.09 मीटर रही, जबकि छठा प्रयास अमान्य रहा। इस स्पर्धा में श्रीलंका के समिथा कोडिथुवाक्कू 64.10 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ चौथे स्थान पर रहे। उन्होंने चौथे प्रयास में यह दूरी हासिल की और 1,001 रजा अंक अर्जित किए। हालांकि, वह भारतीय खिलाड़ियों के पदक क्रम को तोड़ने में सफल नहीं हो सके। भारतीय खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन की खास बात यह रही कि सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक बरकरार रखा, जबकि महेंद्र गुर्जर और संदीप संजय सरगर ने अपने-अपने वर्गों में खेलों के नए रिकॉर्ड बनाते हुए रजत और कांस्य पदक जीते। भारत के लिए यह भाला फेंक स्पर्धा में यादगार सफलता रही। भारत के पैरा एथलीट राकेशभाई भट्ट और संदीप ने एशियाई पैरा खेल-2026 में एथलेटिक्स स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया।

एक नजर

नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले ने देश की आपदाओं में भारत की त्वरित मदद के लिए आभार जताया

काठमांडू,एजेंसी। वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले ने नेपाल में हाल में आई प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भारत की ओर से दी गई सहायता के लिए आभार जताया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में वर्ल्ड समिट-2026 में भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ नेपाल-भारत संबंधों और क्षेत्रीय हितों से जुड़े मुद्दों पर सीधा संवाद किया। 'अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स' सम्मेलन में उन्होंने जलवायु परिवर्तन के कारण रसुवा और भोटेकोशी क्षेत्रों में हाल में आई आपदा तथा वर्ष 2015 के विनाशकारी भूकंप के दौरान भारत की त्वरित सहायता का उल्लेख किया। नेपाल के वित्त मंत्रालय के अनुसार मंत्री वाग्ले ने कहा कि हालिया आपदा और भूकंप के दौरान शुरुआती कुछ घंटों में ही भारत हमारी मदद के लिए पहुंच गया था और उसने असाधारण सहयोग किया। इसके लिए नेपाल बेहद आभारी है। उन्होंने आपदा प्रबंधन, पोषण और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा उपक्षेत्रीय स्तर पर सहयोग को संस्थागत रूप देने की संभावनाओं पर भी सवाल उठाया।

इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि जहां संभव हो, वहां औपचारिक संस्थागत ढांचे का महत्व बना रहता है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को इसका उदाहरण बताया। जयशंकर ने यह भी कहा कि हाल के समय में समान विचारधारा वाले देशों के बीच जरूरत के अनुसार सहयोग करने और परिणाम देने वाली पहलों को प्राथमिकता देने का रुझान बढ़ रहा है।

नेपाल को जलवायु आपदा राहत कोष से 2 करोड़ डॉलर की सहायता को मंजूरी

काठमांडू। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से हुई तबाही की भरपाई के लिए स्थापित लॉस एंड डैमेज फंड ने नेपाल को 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर (करीब 3 अरब 2 करोड़ नेपाली रुपये) का अनुदान देने का फैसला किया है। यह जानकारी कृषि, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने दी। मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि यह राशि 26 अगस्त को

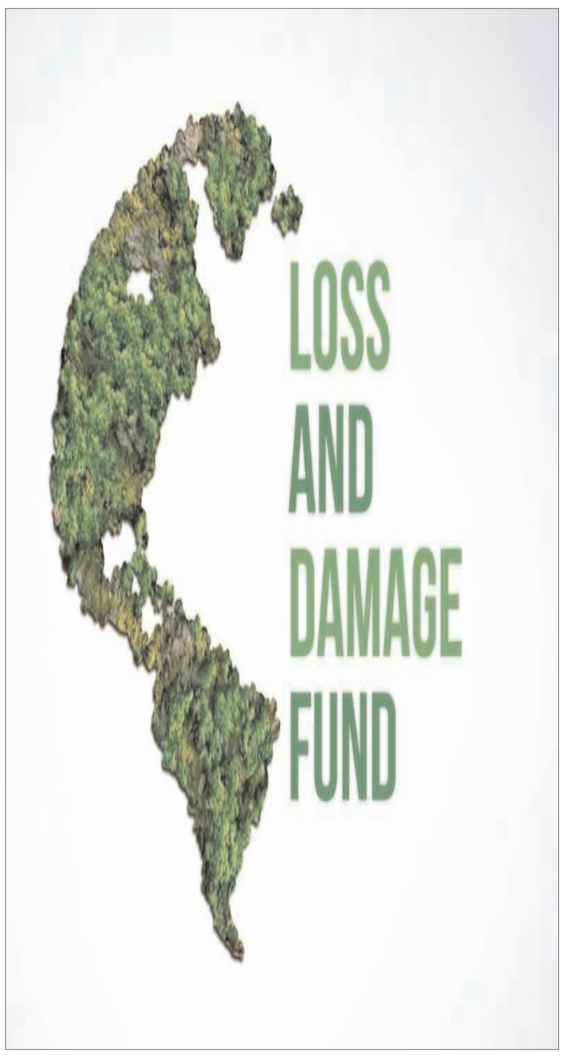

भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित परिवारों और समुदायों को राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इस बाढ़ में 1,500 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 5,000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ से करीब 15 हजार से अधिक परिवारों के 60 हजार से ज्यादा लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से शुरुआती आर्थिक नुकसान लगभग 2 अरब 70 करोड़ डॉलर आंका गया है। वहीं, पुनर्निर्माण के लिए करीब 4 अरब 70 करोड़ डॉलर की आवश्यकता होने का अनुमान है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से 31 अगस्त को नेपाल के वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले और कृषि मंत्री गीता चौधरी ने कोष के बोर्ड से विशेष अनुरोध किया था। इस अनुरोध के आधार पर विकासशील और विकसित देशों, अल्पविकसित देशों, छोटे द्वीपीय विकासशील देशों तथा एशिया-प्रशांत, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और पश्चिमी देशों के समूहों के बोर्ड सदस्यों के बीच विभिन्न चरणों में औपचारिक और अनौपचारिक चर्चा हुई। कृषि मंत्रालय के सहसचिव डॉ. महेश्वर ढकाल ने बताया कि 22 अक्टूबर को हुई बोर्ड की विशेष बैठक में नेपाल को सहायता देने के निर्णय को अंतिम रूप दिया गया। नेपाल की ओर से कृषि मंत्रालय के सहसचिव एवं प्रवक्ता डॉ. ढकाल ने समन्वयक और सहायक की भूमिका निभाई। इस कोष से राशि प्राप्त करने के लिए नेपाल बारबाडोस कार्यान्वयन ढांचे की प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव तैयार कर कोष के समक्ष पेश करेगा। इस बीच, मंत्रालय ने बताया कि कोष की 11वीं बोर्ड बैठक 17 से 19 मार्च 2027 तक काठमांडू में आयोजित की जाएगी। नेपाल के राष्ट्रीय संपर्क अधिकारी और कोष के वैकल्पिक बोर्ड सदस्य डॉ. ढकाल ने कहा कि इस अनुदान के फैसले से नेपाल में जलवायु वित्त के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि नेपाल के जलवायु वित्त के इतिहास में इससे बेहतर और ऐतिहासिक फैसला कोई दूसरा नहीं हो सकता। यह निर्णय नेपाल के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक इसने हानि-नुकसान कोष के अपने इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की है।

फ्रांस में हिंसा पर ट्रंप से भिड़े मैक्रों, बोले- विदेशी नेताओं की टिप्पणियां मूर्खतापूर्ण

पेरिस,एजेंसी। फ्रांस में जारी हिंसक विरोध-प्रदर्शनों और दंगों को लेकर राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। मैक्रों ने फ्रांस की स्थिति पर विदेशी नेताओं की टिप्पणियों को 'मूर्खतापूर्ण और अस्वीकार्य' करार दिया। उन्होंने कहा कि कुछ नेता प्रवासियों और इस्लामवादियों को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि ऐसे दावों के समर्थन में स्पष्ट सबूत नहीं हैं।

रूस के टीवी नेटवर्क रशिया टुडे के अनुसार यह विवाद तब बढ़ा जब ट्रंप ने फ्रांस में हिंसा के लिए मैक्रों सरकार की सीमा और प्रवासन नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि प्रवासियों, जिहादियों और वामपंथी समूहों ने फ्रांस में तबाही मचाई है। इसके जवाब में मैक्रों ने कहा कि विदेशी नेता घटनाओं से जुड़ी जानकारी को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं। मैक्रों ने पत्रकारों से कहा कि फ्रांस में जारी अशांति को लेकर गलत सूचनाएं फैलायी गई हैं, जिनके प्रभाव में आकर कुछ विदेशी नेताओं ने गैर-जिम्मेदाराना बयान दिए। उन्होंने कहा, 'कुछ लोगों का दावा है कि प्रवासियों और इस्लामवादियों की भीड़ ने हम पर हमला कर दिया है, जो पूरी तरह झूठ है। इस संबंध में जब मैक्रों से पूछा गया कि क्या उनकी टिप्पणी ट्रंप के लिए थी, तो उन्होंने कहा कि यह ट्रंप समेत अन्य नेताओं पर भी लागू होती है। दूसरी ओर, ट्रंप ने फ्रांस की सरकार पर सीमाओं की सुरक्षा में नाकाम रहने का आरोप लगाया और यूरोपीय देशों से अपनी सीमाएं बंद करने की अपील की। उन्होंने फ्रांस में हिंसा की तस्वीरों का इस्तेमाल अमेरिकी राजनीति में भी किया और

चेतावनी दी कि ऐसी स्थिति अमेरिका में भी पैदा हो सकती है। फ्रांस में विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत शिक्षकों की कमी और स्कूलों की खराब स्थिति जैसे मुद्दों से हुई थी। बाद में ये प्रदर्शन असमानता, महंगाई और सार्वजनिक सेवाओं में कटौती के खिलाफ व्यापक आंदोलन में बदल गए। प्रदर्शनों के दौरान कई शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं। आगजनी, लूटपाट और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं भी सामने आईं। हिंसा के दौरान करीब 2,400 लोगों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 1,000 पुलिस अधिकारी घायल हुए। सैकड़ों दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा, जबकि कई इमारतों में आग लगा दी गई। कुल आर्थिक नुकसान का अनुमान सैकड़ों मिलियन यूरो बताया गया है। हालांकि, फ्रांसीसी अधिकारियों ने हिंसा के लिए मुख्य रूप से कट्टरपंथी वामपंथी समूहों और अवसरवादी अपराधियों को जिम्मेदार ठहराया है। प्रवासियों की किसी बड़ी भूमिका का स्पष्ट प्रमाण सामने नहीं आया है। दंगों के बीच मैक्रों की विदेश यात्रा को लेकर भी फ्रांस में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि ऐसा करने से घबराहट का संदेश जा सकता था। उन्होंने दावा किया कि सरकार को हालात संभालने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे। दूसरी ओर विपक्षी नेताओं ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि जब पेरिस और दूसरे शहरों में हिंसा हो रही थी, तब राष्ट्रपति देश से बाहर थे। इस वजह से उन्हें 'अनुपस्थित राष्ट्रपति' कहकर निशाना बनाया गया। राजनीतिक दबाव के बीच मैक्रों की लोकप्रियता में गिरावट की बात भी सामने आई है। उनके विरोधियों मरीन ले पेन और ज्यां-ल्यूक मेलनशॉन को सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का मौका मिला है। हिंसा दोबारा भड़कने की आशंका के बीच फ्रांस सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की तैयारी की है। प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने प्रमुख स्थानों पर लोगों के जमावड़े को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंधों की घोषणा की है। सरकार की योजना के तहत लूव्र संग्रहालय और चैंप्स-एलिसीज जैसे प्रमुख स्थलों के आसपास तीन दिनों तक सार्वजनिक जमावड़े पर रोक लगाने की बात कही गई है। इसके अलावा पुलिस की सहायता के लिए आतंकवाद-रोधी सैनिकों की तैनाती की योजना भी सामने आई है। प्रधानमंत्री ने दंगा प्रभावित शहरों के महापौरों के साथ बैठक कर आगे की हिंसा रोकने के उपायों पर चर्चा करने की तैयारी की है। फ्रांस में हिंसा के पीछे विदेशी हस्तक्षेप की संभावना को लेकर भी बहस छिड़ी है।

सऊदी अरब की जेलों में बंद हैं 7,500 बांग्लादेशी : शमा ओबैद

ढाका,एजेंसी। सऊदी अरब की जेलों में करीब 7,500 बांग्लादेशी नागरिक बंद हैं। यह जानकारी बांग्लादेश की विदेश मामलों की राज्यमंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने दी है। उन्होंने बताया कि सरकार सऊदी अधिकारियों के साथ मिलकर वहां बंद अपने नागरिकों से जुड़े मामलों की जानकारी जुटा रही है। साथ ही, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण काम पर वापस नहीं लौट पा रहे बांग्लादेशी प्रवासियों के वीजा और इकामा की अवधि बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बांग्लादेश के अंग्रेज़ी अखबार 'द डेली स्टार' के मुताबिक राज्यमंत्री ने ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शाहिद अहमद का शव प्राप्त करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। अहमद की सऊदी अरब में एक मिसाइल हमले में मौत हो गई थी। शमा ओबैद ने बताया कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण कई बांग्लादेशी कामगार अपने कार्यस्थलों पर वापस नहीं लौट पा रहे हैं। ऐसे में सरकार उनके वीजा और इकामा की वैधता बढ़ाने के लिए सऊदी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है। विदेशों में नौकरी गंवा चुके बांग्लादेशी नागरिकों के पुनर्वास और उन्हें दोबारा रोजगार दिलाने के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इकामा सऊदी अरब में विदेशी नागरिकों को जारी किया जाने वाला निवास परमिट है। इसकी वैधता समाप्त होने पर प्रवासियों को कानूनी और प्रशासनिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सऊदी अरब में हाल ही में दो बांग्लादेशी नागरिकों को फांसी दिए जाने के मामले पर राज्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश सरकार को अब तक इन दोनों नागरिकों के मामलों से संबंधित विस्तृत जानकारी नहीं मिली है। सरकार ने सऊदी अधिकारियों को औपचारिक पत्र भेजकर दोनों मामलों में सुनाए गए फैसलों की प्रतियां मांगी हैं। इसका उद्देश्य घटनाओं के तथ्यों और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना है। शमा ओबैद ने कहा कि प्रत्येक देश की अपनी न्यायिक व्यवस्था होती है और बांग्लादेश दूसरे देश की न्यायिक कार्यवाही में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हालांकि, अपने नागरिकों से जुड़े मामलों की जानकारी जुटाना और उनकी सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार सऊदी अरब में बंद बांग्लादेशी नागरिकों की स्थिति और फांसी से जुड़े मामलों के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के पुराने बयान को लेकर ईरान का हमला, परमाणु नीति पर मांगा जवाब

तेहरान। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया है। अराघची ने मैक्रों के हालिया दावे पर सवाल उठाते हुए 2018 में अमेरिकी कांग्रेस के सामने दिए गए उनके भाषण का हवाला दिया। उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति से अपने पुराने और मौजूदा रुख में स्पष्टता बनाए रखने की अपील की।

ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तसनीम न्यूज़ के अनुसार, अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मैक्रों के पुराने बयान और हालिया टिप्पणी की तुलना की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में मैक्रों ने ईरान परमाणु समझौते का समर्थन किया था और इसे छोड़ने से इनकार किया था, जबकि अब वह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हमेशा ईरान में किसी भी तरह की परमाणु गतिविधि का विरोध किया है। अराघची ने 25 अप्रैल 2018 को अमेरिकी कांग्रेस में दिए गए मैक्रों के भाषण का उल्लेख किया। उस समय फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) का बचाव करते हुए कहा था कि यह समझौता ईरान की परमाणु गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा प्रदान करता है।

अराघची ने अपने पोस्ट में लिखा, '2018 में अमेरिका के ईरान परमाणु समझौते से बाहर निकलने से ठीक पहले, मैक्रों ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने जोर देकर कहा था कि फ्रांस जेसीपीओए नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमने इस पर हस्ताक्षर किए हैं।' उन्होंने मैक्रों के हालिया बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अब फ्रांसीसी राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हमेशा ईरान में किसी भी तरह की परमाणु गतिविधि का विरोध किया है।

ईरानी विदेश मंत्री ने मैक्रों को सीधे संबोधित करते हुए कहा, 'मिस्टर प्रेसिडेंट, अपनी बात तो साफ कर लीजिए। जेसीपीओए यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेन्सिव प्लान ऑफ एक्शन वर्ष 2015 में ईरान और छह प्रमुख शक्तियों— अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी के बीच हुआ था। इसका उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी और सीमाएं लागू करना था, जिसके बदले ईरान को प्रतिबंधों में राहत मिलनी थी।

बांग्लादेश की जेलों में 15 देशों के 407 नागरिक बंद, 168 भारतीयों को वतन वापसी का इंतजार

ढाका,एजेंसी। बांग्लादेश की विभिन्न जेलों में 15 देशों के करीब 407 नागरिक बंद हैं। इनमें से 172 लोग ऐसे हैं जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं या रिहाई के योग्य हैं, लेकिन संबंधित देशों से मंजूरी और वतन वापसी की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण अब भी जेलों में हैं। विदेशी कैदियों में सबसे ज्यादा संख्या भारत और म्यांमार के नागरिकों की है। बांग्लादेश के अंग्रेज़ी दैनिक अखबार 'द डेली स्टार' ने जेल विभाग के हवाले से बताया कि कुल 407 विदेशी कैदियों में 44 दोषी करार दिए जा चुके हैं, जबकि 191 विचाराधीन कैदी हैं। इनमें से किसी भी दोषी को मौत की सजा नहीं सुनाई गई है। बांग्लादेश की जेलों में सबसे ज्यादा 238 भारतीय नागरिक बंद हैं। इनमें से 168 लोग अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन स्वदेश वापसी की औपचारिकताएं पूरी नहीं होने के कारण जेलों में रहने को मजबूर हैं।

इस सूची में म्यांमार दूसरे स्थान पर है। वहां के कुल 133 नागरिक बांग्लादेश की जेलों में बंद हैं। इनमें 33 म्यांमार के नागरिक दोषी करार दिए जा चुके हैं। म्यांमार का केवल एक नागरिक वतन वापसी की प्रतीक्षा कर रहा है। अन्य देशों के कैदियों में नाइजीरिया के छह, पाकिस्तान और मलेशिया के तीन-तीन, तंजानिया और पेरू के दो-दो नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा जॉर्जिया, बहामास, बेलारूस, गुयाना, कांगो, इथियोपिया और थाईलैंड का एक-एक नागरिक जेल में बंद है। जेल अधिकारियों के अनुसार इन विदेशी नागरिकों को ड्रग्स की तस्करी, सोने की तस्करी, धोखाधड़ी, अमेरिकी डॉलर के अवैध कारोबार, पासपोर्ट से जुड़े अपराध, अवैध वॉयस

ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कारोबार और मानव तस्करी जैसे मामलों में गिरफ्तार किया गया था। जेल विभाग के जेलर (मीडिया एवं लॉजिस्टिक्स) मसूद हसन ज्वेल ने बताया कि संबंधित देशों से आवश्यक मंजूरी नहीं मिलने के कारण इन नागरिकों की वापसी नहीं हो पा रही है। जेल प्रशासन इस समस्या से गृह मंत्रालय को लगातार अवगत करा रहा है। विदेशी कैदियों के नाम, पते और अन्य उपलब्ध विवरण ढाका स्थित संबंधित देशों के दूतावासों को भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय के माध्यम से भी पत्राचार किया गया है, लेकिन अब तक अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इस मामले में भारतीय नागरिकों की पहचान और उनकी स्वदेश वापसी की प्रक्रिया एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के कांसुलर विंग के एक अधिकारी के मुताबिक 25 ऐसे भारतीय नागरिकों की पहचान की जा चुकी है, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है और अब भारत लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारतीय मिशन ने विदेश मंत्रालय से इन नागरिकों की वापसी की प्रक्रिया तेज करने और संभावित वापसी तिथियों की जानकारी पहले से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, ताकि भारतीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर जरूरी व्यवस्थाएं की जा सकें। अधिकारी ने बताया कि इसके अतिरिक्त बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने 121 ऐसे कैदियों की सूची भी साझा की है, जिनके भारतीय नागरिक होने और सजा पूरी करने का दावा किया गया है। हालांकि, इनमें से अधिकांश लोगों के संबंध में उपलब्ध जानकारी उनकी भारतीय नागरिकता की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भारतीय उच्चायोग ने ऐसे कैदियों तक राजनयिक पहुंच की मांग की है, जिनकी नागरिकता सत्यापित करने के लिए अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है। अधिकारी के अनुसार कुछ मामलों में पर्याप्त विवरण उपलब्ध हैं, लेकिन नागरिकता की पुष्टि की प्रक्रिया अभी जारी है। उच्चायोग इस संबंध में विदेश मंत्रालय के जवाब का इंतजार कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार के नागरिकों की वापसी के संबंध में प्रतिक्रिया लेने के लिए बांग्लादेश में म्यांमार दूतावास से ईमेल के जरिए कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वहीं, जेल अधिकारियों का कहना है कि सजा पूरी होने के बावजूद विदेशी नागरिकों को लंबे समय तक हिरासत में रखने से प्रशासनिक मुश्किलें बढ़ रही हैं। इससे जेलों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है। साथ ही सुरक्षा कारणों से विदेशी कैदियों को अलग-अलग कोठरियों में रखा जाता है। उनके वार्ड की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जाती है।

पाकिस्तान : शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में आपातकाल का किया बचाव, पीटीआई पर लगाए आरोप

इस्लामाबाद/पेशावर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा (केपी) में आपातकाल और गवर्नर शासन लागू करने के फैसले का बचाव करते हुए इसे बेहद मजबूरी में उठाया गया कदम बताया है। उन्होंने प्रांत में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेतृत्व वाली पिछली प्रांतीय सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच, संघीय सरकार ने प्रांत में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और विकास कार्यों को गति देने के लिए 160 अरब पाकिस्तानी रुपये के विकास पैकेज की घोषणा भी की है।

पाकिस्तान की उर्दू टेलीविज़न चैनल दुनिया न्यूज तथा अंतरराष्ट्रीय मीडिया जिओ न्यूज के मुताबिक, गुरुवार को पेशावर में आयोजित प्रांतीय शीर्ष समिति की बैठक में प्रधानमंत्री ने कानून-व्यवस्था, आतंकवाद विरोधी अभियान और प्रांत में शांति बहाल करने के उपायों की समीक्षा की। बैठक में पाकिस्तान के सेना प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी, उप प्रधानमंत्री इशाक डार, गृह मंत्री मोहसिन नकवी, संघीय मंत्रियों और नवनियुक्त प्रांतीय सलाहकारों ने हिस्सा लिया। बीते 11 अक्टूबर को प्रांत में आपातकाल और गवर्नर शासन लागू होने के बाद यह शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा का यह पहला दौरा था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि प्रांत में सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। उन्होंने पीटीआई पर आतंकवाद से निपटने में लापरवाही बरतने और सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लगभग छह साल पहले खैबर पख्तूनख्वा शांति का केंद्र बन चुका था, लेकिन अब प्रांत में फिर से उग्रवादी हिंसा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। साथ ही कहा कि संघीय सरकार सैन्य नेतृत्व के सहयोग से प्रांत में शांति और समृद्धि बहाल करने के लिए काम करेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि खैबर पख्तूनख्वा को अन्य प्रांतों के समान विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि आतंकवाद के खिलाफ लंबे संघर्ष के बाद पाकिस्तान में शांति स्थापित होने लगी थी, लेकिन पीटीआई के नेतृत्व वाली पिछली प्रांतीय सरकार ने आतंकवादियों की वापसी की अनुमति देकर स्थिति को फिर बिगड़ने दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों और आम नागरिकों ने भारी बलिदान दिए हैं। उनके मुताबिक, इस संघर्ष में लगभग 80,000 लोगों की जान गई और पाकिस्तान को अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। शहबाज शरीफ ने पिछली प्रांतीय सरकार पर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक सुरक्षा की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने दावा किया कि पुलिस के करीब 5,000 पद खाली पड़े रहे और 'सेफ सिटी' परियोजना भी पूरी नहीं की गई। उन्होंने आतंकवाद निरोधक विभाग (सीटीडी) को मजबूत करने, पुलिस प्रशिक्षण और सुरक्षाकर्मियों को आधुनिक हथियार व उपकरण उपलब्ध कराने में कथित लापरवाही को लेकर भी पीटीआई पर निशाना साधा।

पाकिस्तान के ग्वादर में विस्फोट से दहशत, बीएलएफ ने शुरू किया 'ऑपरेशन अलमास'

ग्वादर,एजेंसी। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत के तटीय शहर ग्वादर में गुरुवार को जोरदार विस्फोट और उसके बाद गोलीबारी की खबर सामने आई है। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, विस्फोटकों से लदे एक वाहन के जरिए पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया। इस बीच, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) ने ग्वादर जिले में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर कई हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए 'ऑपरेशन अलमास' शुरू करने का दावा किया है। हालांकि, विस्फोट, गोलीबारी और हमलों में हुए नुकसान को लेकर पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से खबर लिखे जाने तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी। हताहतों की संख्या और सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान की स्वतंत्र रूप से पुष्टि भी नहीं हो सकी है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, गुरुवार को ग्वादर में एक जोरदार धमाका सुनाई दिया, जिसके बाद गोलीबारी की आवाजें आईं। बताया जा रहा है कि विस्फोट की गूंज सुर और पिशुकन इलाकों तक सुनाई दी। प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से आई शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया है कि धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास के कुछ घरों की खिड़कियां टूट गईं और लोगों ने जमीन में कंपन महसूस किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विस्फोटकों से लदे वाहन का इस्तेमाल सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने के लिए किया गया। हालांकि, घटना के सटीक घटनाक्रम, हमले की जिम्मेदारी और संभावित नुकसान के बारे में अभी विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। बीएलएफ ने एक बयान जारी कर ग्वादर जिले में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और उनसे जुड़े ठिकानों पर कई हमले करने का दावा किया है। संगठन के प्रवक्ता मेजर ग्वहराम बलूच के अनुसार, 22 अक्टूबर को ग्वादर जीरो पॉइंट स्थित फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनाइजेशन (एफडब्ल्यूओ) के मुख्य शिविर को निशाना बनाया गया। प्रवक्ता ने दावा किया कि इस अभियान में संगठन की 'सड्डो ऑपरेशनल बटालियन' (एसओबी) और अन्य इकाइयों के लड़ाके शामिल थे। संगठन ने कहा कि विभिन्न स्थानों पर झड़पें जारी हैं और उसने इन्हें 'ऑपरेशन अलमास' नाम दिया है। अपने दूसरे बयान में दावा किया कि ग्वादर में हुई झड़पों के दौरान पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस (एमआई) के एक कैप्टन और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप (एसएसजी) के कई जवान मारे गए हैं। संगठन ने यह भी दावा किया कि उसके लड़ाकों ने ग्वादर जीरो पॉइंट स्थित एफडब्ल्यूओ शिविर पर कब्जा कर वहां अपना झंडा फहरा दिया। इसके अलावा, मजानी पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने और वहां से सरकारी हथियार तथा अन्य उपकरण कब्जे में लेने का दावा भी किया गया है। इन झड़पों में एक पुलिस अधिकारी की भी मौत हुई है। हालांकि, इन दावों की पुष्टि के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बीएलएफ ने गाबद इलाके में पाकिस्तानी सेना के एक काफिले पर हमला करने की जिम्मेदारी भी ली है। संगठन का दावा है कि हमले में एक वाहन नष्ट हो गया और कई सैन्यकर्मी मारे गए या घायल हुए।

एक नजर

स्नातक एवं शिक्षक विकसित और समृद्ध बिहार के पक्ष में: नीतीश कुमार

पटना,एजेंसी। जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पार्टी कार्यालय पहुँचकर विधान परिषद् की आठ सीटों के लिए स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में हो रहे मतदान की जानकारी ली। उन्होंने इस दौरान वाररूम का निरीक्षण किया और मॉनिटरिंग टीम से क्षेत्रवार जानकारी ली। मौके पर उन्होंने संगठन के साथियों से भी उन्होंने फीडबैक लिया। साथ ही उपस्थित कार्यकर्ताओं से भी आत्मीय मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान विधान परिषद् में सत्तारूढ़ दल के उपनेता ललन कुमार सर्राफ एवं राष्ट्रीय चुनाव पदाधिकारी एवं पूर्व सांसद अनिल प्रसाद हेगड़े उनके साथ मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने इससे पहले आज सुबह अपने आवासीय कार्यालय 7, सर्कुलर रोड पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा एवं विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता ललन कुमार सर्राफ से मतदान संबंधी जानकारी ली। इसके उपरांत उन्होंने निर्णय लिया कि पार्टी कार्यालय में विधान परिषद् चुनाव की मॉनिटरिंग कर रहे पदाधिकारियों से भी व्यक्तिगत रूप से मिलकर फीडबैक लेंगे। नीतीश कुमार ने मतदान समाप्ति के उपरांत कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आठों सीटों पर न्याय के साथ विकास के पक्ष में मतदान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में स्नातक एवं शिक्षक ही मतदाता होते हैं और वे भलीभांति जानते हैं कि बिहार की एनडीए सरकार ने पिछले 21 वर्षों में शिक्षा समेत सभी क्षेत्रों में कितने कार्य किए हैं। वे निश्चित तौर पर अपना मत विकसित और समृद्ध बिहार के लिए देंगे।

ऐतिहासिक 'बोल्ला रक्षाकाली पूजा' की तैयारियां शुरू, 27 नवंबर को होगा मुख्य पूजन और भव्य मेला

दक्षिण दिनाजपुर। जिले की ऐतिहासिक और उत्तर बंगाल की लोक-संस्कृति के प्रमुख केंद्र मानी जाने वाली 'बोल्ला रक्षाकाली पूजा' की तैयारियां आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी हैं। परंपरा के अनुसार, विजयादशमी के बाद पड़ने वाले पहले शुक्रवार सुबह मंदिर परिसर के पास स्थित जलाशय से देवी की पवित्र प्रतिमा का ढांचा (काठामो) निकाला गया। इसके बाद दूध से पवित्र ढांचे का अभिषेक कर विशेष पूजा का आयोजन किया गया। पूजा में देवी मां को महाभोग के रूप में 'छप्पन भोग' अर्पित किया गया। ढांचा पूजा (काठामो पूजा) को लेकर गुरुवार रात से ही मंदिर परिसर से लेकर स्नान घाट तक के पूरे रास्ते को आकर्षक फूलों से सजाया गया था। देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालुओं के जयकारों से पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होते ही पूरे इलाके में उत्सव का माहौल बन गया है।

लोक मान्यताओं के अनुसार, देवी रक्षाकाली की मुख्य पूजा रास पूर्णिमा के ठीक बाद आने वाले शुक्रवार को होती है। इस बार 27 नवंबर को मां महामाया की मुख्य पूजा और चार दिवसीय विशाल मेले का आयोजन होगा।उत्तर बंगाल के सबसे बड़े सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में शामिल बोल्ला मेले में हर साल न केवल पश्चिम बंगाल और भारत के अन्य राज्यों से, बल्कि पड़ोसी देशों— बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। चार दिनों तक चलने वाले इस विशाल धार्मिक महोत्सव और मेले को शांतिपूर्ण व सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पूजा समिति के संयुक्त तत्वावधान में व्यापक कार्य योजना बनाई जा रही है। 27 नवंबर को होने वाले इस महापर्व को लेकर पूरे उत्तर बंगाल में भारी उत्साह देखा जा रहा है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का रांची में भव्य स्वागत, ढोल-नगाड़ों और झारखंडी नृत्य से गूंज उठी राजधानी

रांची,एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के झारखंड आगमन पर राजधानी रांची में पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह और उमंग देखते ही बना। भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती पर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष का रांची एयरपोर्ट पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने झारखंड की पारंपरिक संस्कृति, ढोल-नगाड़ों, पारंपरिक नृत्य और पुष्पवर्षा के साथ भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में एयरपोर्ट परिसर और राजधानी के विभिन्न चौक-चौराहे भाजपा के झंडों, बैनरों एवं पोस्टरों से सजे नजर आए।

जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष एयरपोर्ट के निकासी द्वार से बाहर आए, वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। पूरा परिसर 'नितिन नवीन जिंदाबाद' के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। रांची एयरपोर्ट से राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधे भाजपा के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। यहां भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की ओर से उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यालय परिसर में स्थापित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष तीन दिवसीय झारखंड प्रवास पर आए हैं। 24 अक्टूबर को वे भाजपा झारखंड प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे और पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन

करेंगे। इस दो दिवसीय कार्यसमिति बैठक में राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों, संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी रणनीति से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश एवं जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। रांची एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने वालों में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, मधु कोड़ा, राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री सौदान सिंह, झारखंड़ प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल, प्रदेश सह-प्रभारी निवेदिता सिंह, राष्ट्रीय मंत्री प्रदीप वर्मा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ, सहित सैकड़ों की संख्या में पुरुष-महिला नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

उप्र विधान परिषद चुनाव : 11 सीटों पर 152 उम्मीदवारों का भाग्य बैलट बॉक्स में बंद, 55.24 फीसदी हुआ मतदान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों को मिलाकर कुल 11 सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। सभी सीटों पर कुल 55.24 फीसदी मतदान हुआ है। मतदान सुबह आठ बजे से अपराह्न चार बजे तक चला। गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और आगरा जैसे कुछ जिलों में गड़बड़ी के आरोप-प्रत्यारोप के साथ शांतिपूर्ण ढंग से मतदान सम्पन्न हुआ। इसी के साथ 152 उम्मीदवारों का भाग्य बैलट बक्से में कैद हो गया है। 27 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सुबह आठ बजे से अपराह्न चार बजे तक उत्तर प्रदेश की 11 एमएलसी सीटों पर 55.24 फीसदी मतदान हुआ है। लखनऊ खण्ड स्नातक सीट पर 38.02 फीसदी, वाराणसी खण्ड स्नातक पर 41.01, आगरा खण्ड स्नातक 51, मेरठ खण्ड स्नातक में 39.81 और इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक सीट पर 41.40 फीसदी मतदान हुआ है। वहीं, लखनऊ खण्ड शिक्षक सीट पर 50.92 फीसदी, वाराणसी खण्ड शिक्षक 68.21, आगरा खण्ड शिक्षक 63.84, मेरठ खण्ड शिक्षक 60.80, बरेली मुरादाबाद खण्ड शिक्षक 73.69 और गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक क्षेत्र पर

79.01 फीसदी मतदान हुआ है।

उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों की निगरानी में मतदान केंद्रों पर त्रीस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया था। ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न होने पाए। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के इस चुनाव में प्रदेश भर में 14 लाख 81 हजार 310 मतदाता हैं। मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए आयोग द्वारा 11 प्रेक्षक, 1041 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 456 जोनल मजिस्ट्रेट भी तैनात किये गये थे। इसके साथ ही मतदेय स्थलों पर माइक्रो आब्जर्वर की तैनाती के साथ ही वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गयी थी।

उत्तराखंड 2027-28 में 500 नर्स और वार्ड बॉय को विदेश में रोजगार दिलाने का लक्ष्य

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2027-28 में प्रदेश के 500 नर्स और वार्ड बॉय को विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने संबंधित अधिकारियों को पश्चिम एशिया, पश्चिमी यूरोप, एस्टोनिया और खाड़ी देशों में स्वास्थ्यकर्मियों के लिए रोजगार की संभावनाएं तलाशने तथा आवश्यक योग्यता और प्रशिक्षण संबंधी शर्तों का अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शुक्रवार को निजी विश्वविद्यालयों में नर्सिंग पाठ्यक्रमों के संचालन के संबंध में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक हुई। इसमें नर्सिंग शिक्षा के निर्धारित मानकों, स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता और नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कर्मियों के कौशल विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि निजी विश्वविद्यालयों में नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए शुरुआती चरण में कुल 73 आवेदन प्राप्त हुए थे। जांच के बाद इनमें से छह आवेदन समिति के समक्ष विचार के लिए योग्य पाए गए। समिति ने पांच आवेदनों को नर्सिंग पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए योग्य माना, जबकि एक आवेदन को अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। बर्द्धन ने अधिकारियों से कहा कि विदेशों में रोजगार के इच्छुक युवाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और कौशल विकास की व्यवस्था पर काम किया जाए। उन्होंने संबंधित देशों में नर्सिंग और पैरामेडिकल कर्मियों की मांग, शैक्षणिक योग्यता, भाषा दक्षता और अन्य पात्रता शर्तों का आकलन करने को कहा। मुख्य सचिव ने प्रदेश में नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का व्यवस्थित आंकड़ा तैयार करने पर भी जोर दिया। उन्होंने बड़े चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध कर्मियों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, विशेषज्ञता और कौशल से संबंधित जानकारी संकलित कर डाटा बैंक बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप चिकित्सा मानव संसाधन की मांग का आकलन किया जाए और प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्ययोजना तैयार की जाए। इसके साथ ही प्रदेश के अस्पतालों को उनकी जरूरत के अनुसार दक्ष और विशेषज्ञ चिकित्सा कर्मी उपलब्ध कराने के लिए ठोस लक्ष्य निर्धारित करने को कहा। बैठक में निजी अस्पतालों में प्रति बिस्तर निर्धारित मानकों के अनुरूप नर्सिंग स्टाफ और वार्ड बॉय की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि इस संबंध में तय मानकों का सख्ती से पालन कराया जाए, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके। बैठक में सचिव विनय शंकर, अपर सचिव विजय कुमार जोगदंडे, रोहित मीणा, नवनीत पांडेय और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

सनातन चेतना, जन आस्था और वैश्विक गौरव का महापर्व बनेगा दीपोत्सव-2026: मुख्यमंत्री

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव, वाल्मीकि जयंती और चित्रकूट रामघाट के विकास कार्यों की समीक्षा कर दिए समयबद्धता के निर्देश
- 10वें दीपोत्सव में लाखों दीपों से जगमगाएगी रामनगरी, अनेक विदेशी राजनयिक भी बनेंगे साक्षी

लखनऊ,एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में आयोजित होने वाला 10वां दीपोत्सव भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और जनआस्था का भव्य उत्सव होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में वर्ष 2017 में प्रारंभ हुई दीपोत्सव की यात्रा आज वैश्विक पहचान प्राप्त कर चुकी है। इस वर्ष दीपोत्सव के एक दशक पूर्ण होने के अवसर पर राम की पैड़ी सहित संपूर्ण अवधपुरी को गत वर्ष की भांति लाखों दीपों से आलोकित किया जाए। आगामी सात नवंबर को आयोजित होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को निर्देश दिए कि आयोजन की धार्मिक गरिमा, सांस्कृतिक परंपरा और भव्यता के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। श्रद्धालुओं एवं अतिथियों की सुविधा, सुरक्षा, सुगम आवागमन, प्रकाश, स्वच्छता और मार्गदर्शन की समुचित व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए।

मुख्यमंत्री को तैयारियों से अवगत कराते हुए अपर मुख्य सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति ने बताया कि दीपोत्सव का आयोजन तीन प्रमुख चरणों में संपन्न होगा। प्रथम चरण में साकेत महाविद्यालय से भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। शोभायात्रा में रामायण के प्रसंगों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रभु श्रीराम के जीवन आदर्शों को दर्शाया जाएगा। द्वितीय चरण में रामकथा पार्क में प्रभु श्रीराम और माता सीता के स्वरूपों का प्रतीकात्मक आगमन, भरत मिलाप और श्रीराम के राज्याभिषेक से जुड़े कार्यक्रम होंगे। तृतीय चरण में सरयू आरती, दीप प्रज्ज्वलन, राम की पैड़ी पर 200 कलाकारों की प्रस्तुतियां, दो हजार 100 ड्रोनों का आकाश में रामायण आधारित शो, लेजर प्रस्तुति, गोंडा पुल के समीप हरित आतिशबाजी और अंतर्राष्ट्रीय रामलीलाओं का मंचन होगा। लगभग 35 हजार स्वयंसेवक सहभागी होंगे। आयोजन में दो हजार 147 प्रतिभागियों द्वारा सरयू आरती, दो हजार 100 स्वदेशी ड्रोनों के माध्यम से आकाशीय प्रस्तुति, 3डी प्रोजेक्शन और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रमुख आकर्षण होंगे। डिजिटल माध्यमों से दीपोत्सव को पांच करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

समीक्षा में बताया गया कि आयोजन में उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, बिहार, केरल, गोवा और तेलंगाना के लगभग एक हजार कलाकार लोककलाओं और नृत्य परंपराओं की प्रस्तुतियां देंगे। इसके साथ ही 12 देशों के सांस्कृतिक प्रतिनिधियों की सहभागिता प्रस्तावित है। भारत में तैनात विदेशी राजदूतों और विदेशों में तैनात भारतीय राजनयिकों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पदाधिकारियों और अयोध्या के पूज्य संतों के साथ समन्वय कर तैयारियों को अंतिम रूप देने और स्थानीय व्यापारियों व सामाजिक संगठनों का सहयोग लेने के निर्देश दिए। साथ ही, आगामी 26 अक्टूबर को प्रस्तावित महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सभी जनपदों में मंदिरों में वाल्मीकि रामायण का अखंड पाठ, रामायण आधारित प्रस्तुतियां और चित्रकला गतिविधियां कराने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में चित्रकूट स्थित रामघाट के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत दिनों अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्रों का प्राथमिकता के आधार पर पुनर्विकास कराया जाए।

जेपी नड्डा ने की आरएमएल अस्पताल की सेवाओं की समीक्षा

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान (एबीवीआईएमएस) और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल (आरएमएल) की स्वास्थ्य सेवाओं, मरीजों की सुविधाओं, चिकित्सा शिक्षा, शोध और बुनियादी ढांचे के विकास की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, विद्यार्थियों और शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने तथा स्वच्छता और लंबित मामलों के निस्तारण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, आरएमएल अस्पताल में वर्ष 2025 के दौरान 19.4 लाख ओपीडी मरीज पहुंचे। इस अवधि में 82,500 से अधिक मरीजों को भर्ती किया गया, जबकि 96,600 से ज्यादा सर्जरी और अन्य चिकित्सा प्रक्रियाएं पूरी की गईं। अस्पताल में फिलहाल मरीजों के उपचार से जुड़े 30 क्लिनिकल विभाग और आठ प्री-क्लिनिकल एवं पैराक्लिनिकल विभाग संचालित हैं। आरएमएल अस्पताल ने वर्ष 2025 में नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (एनएबीएच) से पूर्ण मान्यता हासिल की। इसके साथ ही यह उपलब्धि प्राप्त करने वाला पहला केंद्रीय सरकार का बहु-विशेषता अस्पताल बना। अस्पताल में उपचार की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए पंजीकरण और मरीजों की प्राथमिक जांच की प्रक्रिया मजबूत की गई है। इसके अलावा क्लिनिकल और प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, चिकित्सा संबंधी घटनाओं की रिपोर्टिंग, दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी और मरीजों से फीडबैक लेने की व्यवस्था भी की जा रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के लाभार्थियों की सुविधा के लिए अस्पताल में योजना से जुड़े कियोस्क की संख्या एक से बढ़ाकर तीन कर दी गई है। योजना के तहत प्री-ऑथराइजेशन अनुरोधों की संख्या वर्ष 2022 में 549 थी, जो 2025 में बढ़कर 1,516 हो गई। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर समीक्षा बैठक में जेपी नड्डा ने अस्पताल में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने डिजिटल स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ ई-प्रिस्क्रिप्शन और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकाधिक उपयोग करने की आवश्यकता बताई। उनका कहना था कि डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में सुधार किया जा सकता है। मंत्री ने प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों के अनुभव और बेहतर कार्यप्रणालियों का उपयोग बड़े स्वास्थ्य ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय करने की भी सलाह दी।

बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा संस्थानों में विद्यार्थियों और शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि पढ़ाई और पेशेवर जिम्मेदारियों से जुड़ा तनाव मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में सहयोगपूर्ण व्यवहार, खुला संवाद और लगातार मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराना जरूरी है। अस्पताल में विद्यार्थियों की नियमित मानसिक स्वास्थ्य जांच और शिक्षकों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जानकारी भी दी गई। नड्डा ने संस्थान में प्रोजेक्ट सारथी लागू करने को प्रोत्साहित किया और इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया। जेपी नड्डा ने अस्पताल में विशेष अभियान 6 के तहत चल रही गतिविधियों की भी समीक्षा की। उन्होंने स्वच्छता को संस्थागत कार्यप्रणाली का स्थायी हिस्सा बनाने, लंबित मामलों को कम करने और रिकॉर्ड के प्रभावी प्रबंधन पर जोर दिया। साथ ही अस्पताल परिसर को स्वच्छ, सुरक्षित और मरीजों के अनुकूल बनाए रखने की आवश्यकता बताई। बैठक में अस्पताल की शोध गतिविधियों और शैक्षणिक योगदान पर भी चर्चा हुई। संस्थान में अब तक 2,200 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए जा चुके हैं। विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अस्पताल की भविष्य की योजना में डिजिटल और मरीज-केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं, विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, सैटेलाइट क्लीनिकों के माध्यम से सामुदायिक पहुंच बढ़ाने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी और पर्यावरण के अनुकूल स्वास्थ्य ढांचे के विकास को शामिल किया गया है। समीक्षा बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक एल.जी. कृष्णा, संयुक्त सचिव जी.एस. चित्रा, एबीवीआईएमएस एवं आरएमएल अस्पताल की निदेशक डॉ. अखिलंदेश्वरी प्रसाद, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. (प्रो.) विवेक दीवान सहित अस्पताल के अन्य अधिकारी और शिक्षक उपस्थित रहे।

दुर्गा पूजा में सियालदह मंडल में 2.63 करोड़ यात्रियों ने किया सफर, यात्री संख्या में 33.44 प्रतिशत की वृद्धि

कोलकाता। दुर्गापूजा के दौरान पूर्व रेलवे के सियालदह मंडल में यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। पूजा के दौरान षष्ठी से दशमी तक छह दिनों में सियालदह मंडल के विभिन्न स्टेशनों से कुल दो करोड़ 63 लाख 39 हजार 698 यात्रियों ने आवागमन किया।

रेलवे सूत्रों के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार यात्रियों की संख्या में लगभग 33.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यात्रियों की इस भारी आवाजाही से रेलवे को भी राजस्व के रूप में बड़ा लाभ होने का अनुमान है। हालांकि, रेलवे की ओर से इस अवधि में हुई कुल कमाई के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। दुर्गापूजा के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए सियालदह मंडल ने षष्ठी से दशमी तक कुल 266 विशेष ट्रेनें चलाईं। अधिकारियों के अनुसार, इन विशेष ट्रेनों के परिचालन से बड़ी संख्या में यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा हुई। सियालदह, दमदम, विधाननगर रोड, सोनारपुर, बालीगंज, रानाघाट और कल्याणी जैसे प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। कल्याणी स्टेशन पर पिछले वर्ष की तुलना में यात्रियों की संख्या

में लगभग 14.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। मंडल के अन्य प्रमुख जंक्शन स्टेशनों पर भी यात्रियों की आवाजाही में बढ़ोतरी हुई। यात्रियों की बढ़ती संख्या के बीच भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने व्यापक इंतजाम किए थे। सियालदह मंडल के मंडल रेल प्रबंधक राजीव सक्सेना के नेतृत्व में वाणिज्यिक, परिचालन, रेलवे सुरक्षा बल, चिकित्सा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी लगातार निगरानी कर रहे थे। प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों को सही दिशा दिखाने, भीड़ को नियंत्रित करने और जरूरत पड़ने पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए रेलवे कर्मचारियों के साथ स्वयंसेवकों को भी तैनात किया गया था। सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली और मेगाफोन के माध्यम से यात्रियों को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे थे, ताकि स्टेशन परिसर में अनावश्यक भीड़ न जुटे और यात्रियों को ट्रेन पकड़ने में परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा, मंडल के वॉर रूम से ट्रेनों के परिचालन और यात्रियों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही थी। रेलवे के इन प्रयासों के बीच दुर्गापूजा के दौरान सियालदह मंडल में करोड़ों यात्रियों की आवाजाही दर्ज की गई। यात्रियों की संख्या में हुई इस वृद्धि ने त्योहार के दौरान उपनगरीय रेल सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया है।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)